हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 नवम्बर, 1986

खण्ड 3, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बधवार, 26 नवम्बर, 1986

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर,	(2) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्न की लिखित उत्तर	(2) 34
विभिन्न विषयों को उठाया जाना –	

(1) तहसील कालका के गांव सकेतड़ी में' जंगली सूअरो द्वारा फसल नष्ट करने समन्धी	(2)35
(2) रंगाई नाले मैं अवरोध के कारण आने वाली बाढ़ से हुई क्षति सम्बधी	(2) 36
(3) नील गाय द्वारा नष्ट की गई फसलों सम्बन्धी	(2) 36
(4) मेवात क्षेत्र के तालाबों में पानी की कमी होने तथा सिंचाई के लिये कोटला झील का उपयोग करने सम्बन्धी	(2)38
(5) अटेली मंडी में सब–ट्रेजरी खोलने सम्बन्धी	(2) 40
वर्ष 1986–87 के सप्लीमैंटरी. एस्टीमेट्स (पहली किश्त) पर चर्चा तथा मतदान–	
(1) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित अनुमानों पर चर्चा	(2) 41
(2) अनुपूरक अनुदानों की मागों पर चर्चा तथा मतदाने	(2) 41

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 26 नवम्बर, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान' सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9. 30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब सवाल होंगे ।

132 K. V. Power Station at Gohana

***1154. Shri Bhalle Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any, proposal under consideration of the. Gov: rnment to construct a 132 K. V. sub-station at Gohana;

(b) if so, whether the construction work of the said sub-station has been taken in hand and

(c) if so, the time by which the said station is likely to be completed and commissioned ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala)

(a) & (b) : Yes, Sir.

(c) The work is almost complete and the sub-station is

likely to be commissioned shortly.

श्री भले राम : स्पीकर साहब, वैसे तो विजली की दिक्कत सभी जगह है लेकिन गोहाना सबडिवीन में अधिक है । यह बड़ी अच्छी बात है कि वहां 132 के० वी० सब–स्टेशन का काम कम्पलीट हो चुका णै । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस महीने या अगले महीने में इहका उदघाटन करेगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें उद्घाटन की कोई बात नई है । यह आलरेडी ट्रायल पर है और अगले हफ्ते या दस दिन में सब–स्टेशन कमीशन हो जायेगा । अब तक गोहाना के एरिया को रोहतक से बिजली मिलती थी । पहले यहां पर 33 के० वी० सबक्टेशन था जिसके कारण गोहाना शहर और आस–पास के गांव को बिजली की काफी दिक्कत थी । इस सब–स्टेशन के कमीशन होने से बिजली की वोल्टेज में और सप्लाई में काफी इम्दूवमैंट हो जायेगी ।

श्री जगदीश नेहरा : क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि हरियाणा में कितने सब–स्टेशन निर्माणाधीन हैं या बिजली बोर्ड के विचाराधीन हैं?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस साल यानी 1986–87 में बिजली बोर्ड ने चालीस करोड़ रुपया इस प्लान में ट्रांसमिशन के लिंए रखा था जिसमें 33 के० वी० सबक्टेशन और टूसरे सब–स्टेशन बनाने थे । इस माली साल के दौरान दो नये सब–स्टेशन

220 के० वी० के बनने थे । एक नारनौल में जिसका 2 1– 11–४6 को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब उद्घाटन कर चुके हैं । दूसरा कैथल में जिसको अरली 1987 में कमीशन करने का प्रोग्राम है और आठ सब–स्टेशन 132 के० वी० के बनने हैं जिनमें से बावल का आलरेडी कमीशन हो चुका है । डिगबा जांटा का मुख्य मन्त्री जी ने अक्टूबर के महीने में कमीशन कर दिया था । गोहाना के बारे में मैंने अभी बताया है कि ट्राइल पर है, मीरान का भी ट्राइल पर बै । पुंडरी, हिसार कैन्ट, मातनहेल और डिग के इस माली साल में पूरे हो जाने चाहिएं । इस साल छः 66 के० वी० सब–स्टेशन कमीशन करने का प्रोग्राम है । उसमें हैदराबाद एसबैसटोज वैस्टर्न फरीदाबाद एस्कोर्ट, फरीदाबाद जनवरी में, भीच अप्रैल में, झाडसेतली अप्रैल में, बसन्तपुर भी इसी दौरान में और एफ० सी० आई० का जनवरी–फरवरी में कमीशन होने का कार्यक्रम है । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय 20 नये 33 के० वी० के सबस्टेशन बनाने का भी प्रोग्राम है और 65 सबस्टेशन 33 के० वी० के आगमैंट करने का प्रोग्राम है । इस वक्त तक जो सब–स्टेशन चालू हो चुके हैं उनमें 132 के० वी० का बावल में, डिगवा जाटां में 33 के० वी० के, झाडूसल, पाबडी, मामुपुर, स्टड फार्म, हिसार में आगमैंट हो चुके हैं । इसी तरह से 220, 120 तथा 66 के० वी० सब–स्टेशनों को भी आगमैंट करने का कार्यक्रम है । 65 सबस्टेशन्ज में से 22 के करीब 33 के० वी० सव–स्टेशन का आगमैटेशन कम्पलीट हो चुका है और बाकी को कम्पलीट करने जा रहे हैं ।

श्री साहब सिंह सैनी : मन्त्री जी ने बताया है कि कहा कहां सबस्टेशन बनाने जा रहे हैं । मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में 132 के० वी० सब– स्टेशन बनाने की जो प्रोपोजल थी, उसे कब तक इम्पलीमैंट किया जायेगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र में इस साल सब–स्टेशन बनाने कॉ कार्यक्रम नहीं है । अगर मैम्बर साहव अलग से सवाल पूछेंगे या असैम्बली के बाहर पता करना चाहेंगे तो इन्फर्मेशन दे देंगे ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब डींग में एक सब–स्टेशन मंजूर हुआ था लेकिन उसकी साइट का झगड़ा था । वह झगड़ा अब निपट गया है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह सब–स्टेशन कब तक शुरू होगा?

चौधरी शमशेर सिंह सूरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अगर एक एक जगह के झगडे की बात पूछेंगे तो मुझे इन्फर्मेशन देनी मुश्किल होगी ।

श्रीमती करतार देवी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि कलानौर में जो 33 के० वी० सबस्टेशन बनना प्रस्तावित था, वह कब तक बन जायेगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : यह इन्फर्मेशन पता करके बतला दूंगा । इस वक्त मेरे पास डिटेल नहीं पै ।

श्री अध्यक्ष : आनरेवल मैम्बर ने गोहाना के बारे में पूछा है और मिनिस्टर साहब ने काफी डिटेल में जवाब दे दिया है । अब मेरा उन्हें यह कहना कि सभी का जवाब दें, ठीक नहीं लगता ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, जो सब–स्टेशन और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है, वह अन–इवन है । कुरुक्षेत्र और करनाल के एरिया में बहुत ज्यादा शार्टेज है थिसके कारण स्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है । इसका मन्त्री महोदय कारण बताने का कष्ट करेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अब स्थिति गम्भीर नहीं बल्कि इम्प्रूव होती जा रही है । जैसे जैसे लोगों की डिमान्ड बढ़ती जा रही है और सहूलियतें बढती जा रही हैं, उससे वोकल ज्यादा हो जाती है । मैं स्थिति के बारे में हाउस को जानकारी देना चाहूंगा । हमारी मन्थली कंजम्पशन जूलाई, 1988 से नवम्बर, 1986 और जुलाई 1985 से नवम्बर 1985 तक इस प्रकार थी–जुलाई, 1985 में टोटल एवरेज कन्जम्पशन एक करोड़ तीस लाख यूनिट थी और जुलाई 1986 में बढ़कर एवरेज एक करोड़ 54 लाख यूनिट हो गई । अगस्त 1985 में एक करोड़ 16 लाख यूनिट थी तो अगस्त, 1986 में बढ़ कर एक करोड़ 87 लाख हो गई । सितम्बर, 1985 में एक करोड़ 44 लाख थी तो –सितम्बर, 1986 में बढ़कर एक करोड़ 64 लाख हो गई । इस तरह से जो छः महीने में एवरेज थी बह एक करोड़ 24 लाख यूनिट थी वह बढ़कर इस साल में एक करोड़ पचास लाख यूनिट हो गई है । यह डेली की एवरेज है । एग्रीकल्चर में सन 1985 में 67 लाख यूनिट रोज की एवरेज थी लेकिन 'जुलाई, 1986 में बढकर 78 लाख

यूनिट हो गई और अगस्त में 53 लाख यूनिट से बढ़कर 92 लाख यूनिट रोज की हो गई । सितम्बर में 73 लाख से बढ़ कर 99 लाख हो गई । जुलाई, 1985 से नवम्बर, 1985 तक एवरेज 61 लाख यूनिट थी जवकि इस साल 81 लाख यूनिट एवरेज है । इसलिये यह बात नहीं हे कि स्थिति गम्भीर होती जा जी है । स्थिति में ये सुधार होता जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को पूरी तरह से ज्ञान है कि इस साल मौनसून टोटली फेल हो गई । पूरे जुलाई और अगस्त महीने में बारिश नहीं हुई लेकिन इसके बावजूद भी पैडी, काटन और गन्ने की क्रोपस पहले सालों से ज्यादा हुई है । इससे साबित होता है कि बिजली की पहले से बेहतर स्थिति है।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, मेरा इस सवाल से ताल्लुक नहीं है क्योंकि मिनिस्टर साहब के बहुत ज्यादा अददोशुमार हैं कि बिजली की पैदावार बड़ी है और कन्जम्पशन भी बड़ी है । मैं आपकी मार्फत पूछना चाहूंगा कि जो यह बि जली वढी है, यह देहात और शहर में तो गई नही है, यह बिजली कहां पर गई है? क्या यह बिजली इन्डस्ट्री सैक्टर में गई हे या एग्रीकल्चर सैक्टर में गई है क्योंकि देहातों में तो बिजली न होने से लोग साढ़े सात बजे ही सो जाते हैं और शहरों में 8– 9 बजे के बाद बिजली आन नही होती, तो यह बिजली किस अदायरे में जा रही है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : मैं आपके द्वारा हाउस को बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सैक्टर में जहां पहले 60 लाख यूनिट बिजली डेली यूज होती थी, आज इस साल में एक करोड़ 10 लाख या

15 लाख यूनिट कन्जयूम हो रही है । आज के दिन सारे वक्तों से ज्यादा बिजली एग्रीकल्चर को दी जा रही नैं । इस वक्त एग्रीकल्चर को 80 लाख यूनिट बिजली जाने लगी है, शायद और भी बेहतर स्थिति हो जायेगी । हमें बढ़ोतरी की अगले हफ्ते या दस दिन में उम्मीद है । जहां तक सरदार लछमन सिंह जी की बात का सम्बन्ध है कि लाइट नहीं लती है, शहरों में शाम को पांच बजे से सुबह आठ बजे तक दी जाती है और दे पहर को साढ़े ग्यारह बजे से दो बजे तक तीन फेज में दी जा रही है, इसमें किसी तरह की बाधा नहीं है । मुकामी तौर पर अगर कोई खराबी हो तो दूसरी बात है । गांवों मैं शाम को चार से पांच बजे तक ड्रिकिंग वाटर के लिए बिजली दी जाती है– और वह भी थी फेज में दी जातीं है और पांच बजे सुबह से नौ बजे तक टू फेज में दी जाती हे । नौ बजे सुबह से तीन बजे तक थे । फेज में बिजली दी जाती है । चार बजे सुबह से छः बजे तक ड्रिकिंग वाटर के लिए लिए थ्री फेज, में बिजली दी जाती है । दिन के वक्त गांव में बिजली की प्राथमिकता नहीं है क्योंकि खेती के लिये और दूसरी चीजों के लिये विजली की ज्यादा जरुरत है । स्टेट में इतनी बिजली नहीं है कि बिना जरुरत के हर वक्त कोई भी व्यक्ति 24 घंटे बिजली इस्तेमाल करता रहे । इतना इन्तजाम हम जरूर कर रहे हैं जिस के अनुसार चाहे एग्रीकल्चर है, या इंडस्ट्री है या डोमैस्टिक है, उनको जरूरत के मूताबिक बिजली पूरी मिलती रहे ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, इस बात का तो सब को पता है कि बिजली में बार–बार फलक्चुएशन होती रहती है चाहे कोई 132

के० वी ० स्टेशन हो या छोटा या बड़ा हो, सब जगह यही हाल है । मैं जानना चाहता हू कि इसका क्या कारण है? एक बार मेरी घरवाली भैस का दूध निकाल रही थी, अचानक ही बिजली चली गयी और हमारा काफी नुक्सान हुआ । मैं जानना चाहूगा कि बार–बार बिजली फेल होने का क्या कारण है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, कारण तो बहुत से हों सकते हैं । बिजली बोर्ड के लैवल पर तो एक कारण यही है कि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम अभी स्ट्रैंन्थन्ड नहीं है । उसको स्ट्रैन्थन करने– में टाइम लगेगा । यह काम एक दिन में या एक साल में तो ही नहीं सकता । भले राम जी की भैस के बिगड़ने का कारण यह हो सकता है कि इन्होने बिजली से कोई छेड़छाड़ की हो और बिजली चली गयी हो या लीक हो गयी हो ।

Shortage of Electricity

***1176. Shri Jagdish Mehra :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any shortage of electricity in the State; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to remove the shortage ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjowala) : Yes, Sir. The availability of Power in the State is inadequate

The following steps are being taken to meet with the shortage of electricity—

(1) Commissioning of new generation units at State's

own generation projects.

(2). Securing maximum power from Central/Common Projects against our shares,

(3) improvement in generation at the State's awn generation projects.

Securing special assistance of power from Centre.

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अपने जवाब में जो कहा है उसको स्पैसिफाई करें कि इससे इनका क्या मतलब है? पहले इन्होने यह कहा है Commissioning of new generation units at State's own generation projects. स्टेट प्रोजैक्ट्स में कौन–कौन से यूनिट कमीशन होगे । फिर कहते हैं Securing maximum power from Central/Common Projects against our shares. कितना अधिक शेयर लेंगे और तीसरी बात इन्होंने यह कही है कि Improvement in generation at the State's own generation projects. इसमें कौन–कौन सी इम्प्रूवमैंट आएंगे और कैसे लायेंगे? चौथी बात कहते हैं Securing special assistance of power from Centre इसमें कौन सी और किस टाईप की स्पेशल असिस्टैंस सैन्टर से सिक्योर करेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सर, आप ही देखिये, इन्होने एक सवाल की बजाये चार सवाल इकट्ठे ही पूछ लिये हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप जितना जवाब दे सकते हैं, दे दें, बाकी अगली बार सप्लीमैंट्री के जवाब में बता दें ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सर, पहले तो इन्होने यह पूछा है कि कौन– कौन से और नये यूनिट स्टेट्स प्रोजैक्ट्स में राड किये जायेंगे । एक तो पानीपत का 110 मैगावाट का एक यूनिट जिसकी कमिशनिंग 1985 के अन्त में की गयी थी, वह 1987 तक कामर्शियल जनरेशन शुरू कर रहा है । इसके साथ ही पानीपत में यूनिट नं० 4,110 मैगावाट का जो है, वह दिसम्बर, में ट्रायल जनरेशन शुरू कर देगा और अप्रैल या मई तक कामर्शियल जनरेशन शुरू कर देगा । इसी प्रकार से यमुना नगर हाइड्रो–इलैक्ट्रिक जनरेशन का 8 मैगावाट का यूनिट ए–पावर हाउस काम कर रहा है । बी–पावर हाउस फरवरी या अप्रैल में चालू हो जायेगा । इसी प्रकार 210 मैगावाट का फिफ्थ यूनिट पानीपत में 1988–89 में कमिशन हो जायेगा । इसके अलावा, यमुना नगर में एक थर्मल पावर यूनिट लगाने का भी विचार है, लेकिन उसमें अभी टाईम लगेगा ।

श्री कैथल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि ये–ये मइयर्ज पावर–सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिये ले रहे हैं । अपेरैटली ये उसके लिये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों नाथपा झाकडी प्रोजैक्ट यह कह कर छोड़ दिया गया कि हमारे पास रिसोर्सिज नही हैं । अब उस प्रोजैक्ट को वर्ल्ड बैक असिस्टैसं से बनाया जा रहा है । क्या मन्त्री महोदय दोबारा उस बात पर मीर करेंगे कि हम ही क्यों न वर्ल्ड बैंक की असिस्टैसं से उस प्रोजैक्ट को बनायें ताकि हमारा उसमें शेयर पूरा रहे ? आपको पता है कि थर्मल पावर स्टेशन्ज तब

कामयाब होते हैं नार यह रिक्यायरमैंट से कहीं ज्यादा कैपेसिटी के लगे हुए हों ताकि उनको मेनटेनैस के लिये टाईम–टू–टाईम क्लोज किया जाये क्योंकि इनमें अक्सर कोई न कोई प्रौब्लम पैदा होती रहती है । मेरा सवाल यही है कि क्या उस पर दोबारा विचार किया जायेगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, यह कहना गलत है कि हमने यह कह कर उस प्रोजेक्ट कौ छोड़ दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है । यह बात ठीक नहीं है ।

श्री कंवल सिंह : आपने ही ऐसा हाउस में कहा था ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सर, मैंने ऐसा कोई व्यान नही दिया था । इस बारे में भारत सरकार ने यह अमैडमैंट की थी कि हिमाचल और हरियाणा के पास इतने रिसोर्सिज नहीं हैं कि वे एक हजार करोड़ रुपया अपने रिसोर्सिज में से लगा सकें । इसलिये यह फैसला लिया गया, बावजूद हमारी इन्सिस्टैसं के कि इसमें हमारा शेयर रखा जाये, इसको एन ० एच ० पी ० सी ० बनायेगी । वह फैसला करते वक्त हरियाणा सरकार ने एक बात यह कही थी कि हमारा शेयर 40 परसैन्ट के करीब होना चाहिये हमारा प्रैफरैन्स बेसिज पर पावर खरीदने का राईट होना चाहिये । इस बात का हमें जबानी तौर पर आश्वामन दिया गया है कि हमें प्रैफरैस मिलेगा ताकि हमारी बिजली की कमी पूरी हो सके । जहां तक दूसरे यूनिट्स का सवाल धै, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है यमुना नगर में 800 मैगावाट के करीब यू निट्स सैवन्थ फाईव इयर प्लान में लगाने का कार्यक्रम है । इसके लिये हाई

लेवल पर गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास यह बात पैंडिंग है । हमें उम्मीद है कि इसका फैसला जल्दी ही हो जायेगा । इससे आने वाले सालों में, हमारे प्रोजैक्शन्ज को देखते हुए हमारी समस्या काफी हद तक मीट हो जायेगी । इसी दौरान जैसे–जैसे सैन्ट्रल प्रोजैक्ट्स कमिशन होंगे, उनसे भी हमारा शेयर मिलना शुरू हो जायेगा ।

चौधरी साहब साहब सैनी : मन्त्री महोदय ने बिजली की कमी को दूर करने के लिये सरकार जो–जो स्टैप्स ले रही है, वह बताये हैं । हमारे एरिया में जो बिजली आती है वह संगरौली–हिमाचल प्रदेश से आती है । बह सारे अम्बाला जिले में व कुछ रादौर के एरिया को फीड करती है । हम वह बिजली पूरी तरह से कम्म नही कर पाते । लाडवा तक अगर रादौर से एक लाईन कंस्ट्रक्ट कर दी जाये तो लाडवा को भी पूरी बिजली मिल सकती है और यह बिजली पूरी तरह से कंज्यूम हो सकती है । मन्त्री महोदय वहां पर गये भी थे लोगों ने यह मांग इनके सामने रखी थी कि इम सिस्टम को जल्दी से जल्दी बताया जाये, क्या यह ऐसा करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष : यह बात मेरे नोटिस में भी आई है कि हमें जौ हिमाचल से बिजली मिलती है वह हम पूरी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वेस्ट हो जाती है। मैंने औफिसर्ज से भी बात की है लेकिन यत् बात कंफ्यूजन में है ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, संगरौली से जो हमारा बिजली का शेयर है, वह डेढ दो साल पहले रेवेक्यूट करके

गिरी बाटा लाइन बनाई थी। उस बिजली को लाकर यमुनानगर और जगाधरी का जो एरिया है, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं । यह कहना कि हम बिजली का पूरा इस्तेमाल नहीं करते या वह बिजली वेस्ट जा रही है, यह बात बिछल नहीं है । स्पीकर साहब, वह बिजली ज्यादा स्टेबल है । स्टेबल इस सैसं में कि बी ० बी ० एम ० बी ० के जो सब–स्टेशन्ज हैं, चाहे वे अम्बाला में हैं या कुरुक्षेत्र में हैं, जब उनकी मशीनों पर ज्यादा लोड पडता है या कोई और प्रोबलम आती है तो वे हमारी मशीनों को औफ कर देते हैं । संगरोली की बिजली ट्रिप नहीं होती, भाखड़ा की ट्रिप करती है । संगरौली की बिजली ट्रिप नही करती जब तक कि हम पूरी बिजली न से ।

श्री अध्यक्ष : दरअसल हमारे औफिसर्ज ने बताया कि इस लाईन को शाहबाद से कनैक्ट करना था, लाडवा से कनैक्ट करना था । यह काम डिले होता रहा और बिजली वैस्ट होती रही । यह औफिसर्ज की बात है, आप औफिसर्ज से पता कर ले ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अगर आप चाहें तो यह इंफरमेशन ' पता करके मैं हाउस में बता सकता हूं ।

चौधरी सूबे सिंह पुनिया : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर मिनि थर्मल यूनिट लगाने का सरकार का विचार है जिससे बिजली की कमी पूरी की जा सके?

स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि इस समय ट्रांसफारमर्ज को ठीक करने की वर्कशौप धूलकोट में है । अक्सर ऐसा होता है कि

ट्रांसफारमर ठीक करने के बाद जब उसको लेकर जाते हैं तो वह रास्ते में ही खराब हो जाता है । इस दिक्कत को दूर करने के तिये अगर जिला स्तर पर वर्कशौप खोल दी जाएं तो समस्या काफी हल हो सकती है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर ट्रांसफारमर्ज को ठीक करने के लिये वर्कशौप खोलने का सरकार का कोई विचार है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, यह ट्रांसफारमर्ज के बारे में सवाल नही है । मैम्बर साहब ने जो मिनि थर्मल प्लांट जिला स्तर पर खोलने का प्रश्न किया है, उसके बा रें में मैं बता देता हूं । स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड ने गवर्नमैंट आफ इंडिया को आठवें प्लान में दो सौ बीस मैगावाट के सब–स्टेशन्ज जींद, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल आदि में लगाने का प्रोग्राम सबमिट किया है । यह केस उन जगहों के लिये सबमिट किया गया है जहां बिजली बोर्ड यह सोचता है कि भविष्य ग्रे बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ने की संभावना है ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, पिछला महीना सोइंग सीजन का था । नारनौल की सारी तहसील में पिछले – महीने बिजली की हालत यह रही है कि अगर किसान ने खेत की एक क्यारी भरी है और वह दूसरी क्य भरने गया तो इतनी देर में बिजली चली गई और जहां पानी दिया था वह भी उतनी देर में सूख गया । खैर, पिछला महीना तो निकल गया लेकिन आगे आने वाले चार पांच महीनों में अगर बिजली की सप्लाई रेगुलर नहीं रही, किसानों को पूरी बिजली नहीं

मिली तो हम लोग ज्या हो जाएंगे । क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कोई कदम उठाने का विचार रखते हैं?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इस समय व्हीट की बिजाई का सीजन है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इस समय बिजली की पूरी सप्लाई की जाए । राव साहब ने नारनौल की बात कही है कि वहां पर बिजली की सप्लाई ठीक नहीं रही है । स्पीकर साहब, मैं अप्रैल, 1985 से लेकर जून 1985 तक और अप्रैल, 1986 से लेकर जून, 1986 तक नारनौल में जो बिजली सप्लाई की गई उसकी फिगर बता देता हूं । अप्रैल, 1985 से जून, 1985 तक नारनौल को रोजाना 4. 18 लाख यूनिट बिजली मिली और 1986 में इन्हीं महीनों में 6. 11 लाख यूनिट रोजाना बिजली मिली है । इस तरह से प्रोग्रेसिवली बिजली की सप्लाई में इंक्रीज हुई है । यह बात ठीक है कि हमारे पास इतनी बिजली नहीं है कि हम हर डिमांड को पूरी कर सकें लेकिन् किसी भी सैक्टर की जो मिनिमम डिमांड है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

Wood purchased/sugarcane unshed etc. in Cooperative Sugar Mills

***1173. Chaudhri Azmat Khan :** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) the details of the wood purchased for use in the Cooperative Sugar Mills Palwal, Panipat & Karnal, separately, during the years 1984-85 and 1985-86, together with the cost thereof ;

(b) the quantity of sugarcane crushed and the sugar produced in each of the said mills during the above period ;

(c) the category-wise number of persons recruited on permanent/ temporary basis in the Palwal Sugar Mills during the period as referred to in part (a) above and whether the prescribed procedure was followed while making the said recruitment; and

(d) the number and names together with addresses of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other minority communities appointed as a result of the recruitment as referred to in part (c) above ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री प्यारा सिंह) :

(क) विवरण विधान सभा के पटल पर रखा जाता है अनुबन्ध (क) ।

(ख) विवरण विधान सभा के पटल पर रखा जाता है अनुबन्ध (ख) ।

(ग) किरण विधान सभा के पटल पर रखा जाता है अनुबन्ध (ग)

(घ) विवरण विधान सभा के पटल पर रखा जाता है अनुबन्ध (घ) ।

अनुबन्ध (क)

1. मात्रा क्विटलों में ।

2. कीमत रुपयों में ।

क्र संख्या	सहकारी चीनी मिल का नाम	1984–85 में जो लकड़ी खरीदी गई		1988–86 में जो लकड़ी खरीदी गई	
		मात्रा (क)	कीमत (ख)	मात्रा (क)	कीमत (ख)
1.	दी पलवल सहकारी चीनी मिल लि०, पलवल	18277.48	899105.01	24412.85	1252248.31
2.	दी पानीपत सहकारी चीनी मिल लि०, पानीपत	12774.28	722537.98	145०4.45	77925.47
3.	दी करनाल सहकारी चीनी मिल लि० करनाल	2969.30	154100.98	7490.60	397722.87

अनुबन्ध (ख)

(आकड़े लाख क्यिंटलों में)

क्रम सं०	सहकारी चीनी मिल का नाम	1984 –85		1985–86	
		गन्ना जो पीड़ा गया	चीनी जो बनाई	गन्ना जो पीड़ा गया	चीनी जो बनाई गई
1.	दी पलबल सहकारी चीनी मिल लि०, पलवल	0.45	0.04	4.45	0.34
2.	दी पानीपत सरकारी चीनी मिल लि०, पानीपत	10.87	0.91	13.06	1.13
3.	दी करनाल सहकारी चीनी मिल लि०, करनाल	16.53	1.53	15.56	1.50

अनुबन्ध (घ)

क्र सं०	श्रेणी	पलवल सहकारी चीनी मिल लि० पलवल में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या	
		1984—85	1985— 86
1.	स्थाई	197	27
2.	मौसमी	284	112
3.	अस्थाई	32	2
	कुल	513	141

2. उपरोक्त भर्तियों के लिये निर्धारित उचित क्रिया विधि अपनाइं गई ।

अनुबन्ध (घ)

वर्ष 1984– 85

क्रम सं ०	भर्ती किये गये व्यक्तियों के नाम	पता	पद	श्रेणी
				अनसूचित जाति / अन–सुचित जन जाति / पिछडे वर्ग
1	2	3	4	5
1	दाल चन्द	गांव अलिकी, डा ० धतीर, फरीदाबाद	सेवक	पिछड़ी श्रेणी

2	दौलत राम	गांव व डा ० बामणी खेडा, फरीदाबाद	स्टोर बुआए	अनुसूचित जाति
3	शिव हरि	–उपरोक्त–	–उपरोक्त–	–उपरोक्त–
4	किशन लाल	गांव व डा ० बधौली, पलवल, फरीदाबाद	चौकीदार	–उपरोक्त–
5	रोहतास	गांव व डा ० बधौली, फारुखनगर, गुड़गांव	–उपरोक्त––	पिछड़ी श्रेणी
6	गणपत	–उपरोक्त–	–उपरोक्त––	अनुसूचित जाति
7	रतिराम	–उपरोक्त–तेजनगर, गुड़गांव	–उपरोक्त––	–उपरोक्त–
8	देवी सहाई	गांव व डा० मधौलो बामली खेड़ा, पलवल	मजदूर	अनुसूचित जाति
9	छत्तर पाल	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––

10	रामप्रसाद.	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––
11	लालचन्द	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––
12	किशन चन्द	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––
13	राजेन्द्र कुमार	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––
14	रुप चन्द	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––
15	फूल चन्द	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––
16	गजराज	–उपरोक्त– गायलषुर, पलवल, फरीदाबाद	कुली	पिछड़ी जाति
17	प्रेम चन्द	–उपरोक्त– बामणी बेडा, पलवल	कुली	अनुसूचित जाति
18	ऊमा शंकर	नांव व डा ० बामणी खेड़ा, पलवल	कुली	–उपरोक्त––
19	ईतवारी	–उपरोक्त–	कुली	–उपरोक्त––

20	हरि सिंह	गांव व डा० बामणी खेड़ा, पलवल	कुली	–उपरोक्त––
21	हीरा लाल	–उपरोक्त––	कुली	–उपरोक्त––
22	बैमानी	–उपरोक्त––	कुली	–उपरोक्त––
23	निरंजन लाल	–उपरोक्त––	कुली	–उपरोक्त––
24	दीप राम	–उपरोक्त––	कुली	–उपरोक्त––
25	भगत सिंह	–उपरोक्त––	कुली	–उपरोक्त––
26	लाखू	–उपरोक्त––	कुली	–उपरोक्त––
27	खेम चन्द	–उपरोक्त––	कुली	पिछड़ी श्रेणी
28	उदय पाल	–उपरोक्त––	कुली	अनुसूचित जाति
29	खेम चन्द	–उपरोक्त––	कुली	पिछड़ी श्रेणी
30	इन्द्र	–उपरोक्त––	कुली	अनुसूचित जाति

31	सुमेर	–उपरोक्त––	कुली	–उपरोक्त–
32	धर्मवीर	गांव व डा० बामणी खेड़ा, पलवल	कुली	अनुसूचित जाति
33	गिरधारी	–उपरोक्त–	कुली	–उपरोक्त –
34	अलिम	–उपरोक्त–	कुली	पिछड़ी श्रेणी
35	गनेश प्रशाद	गांव व डा० कुनआ, गोपालगंज (बिहार)	खलासी	पछड़ी श्रेणी
36	जुगल किशोर	––उपरोक्त–– पूर्वावखालंबा, सिवन (बिहार)	खलासी	अनुसूचित जाति
37	सुर्दशन	–उपरोक्त– धीछप्परा, पश्चिम (बिहार)	खलासी	पिछड़ी श्रेणी
38	राय बालक	–उपरोक्त– कासोनी, सिबन (बिहार)	खलासी	–उपरोक्त––
39	रतन लाल	–उपरोक्त–– मेवाला, मुजफर नगर	खलासी	–उपरोक्त–

		(यू०पी०)		
40	राम देव	गांव व डा० रामपुर, दियोरिया (यू ० पी०)	खलासी	पिछड़ी श्रेणी
41	रामाशफर	गांव व डा० बैकी, फुलबारी (यू० पी०)	आई ० डी /एफ ० डी ०	–उपरोक्त–
42	सेधा राम	गांव व डा० भौराकलां, गुड़गांव	फीड पम्प अटैन्डैट	अनुसूचित जाति
43	रामकुमार	गांव व डा० बामणी खेड़ा, पलवल, फरीदाबाद	मोटर अटैण्डेट	पिछड़ी श्रेणी
44	प्रकाश चन्द	गांव व डा० भरवारी, बुलन्द शहर (यू ० पी०)	मोटर अटैंडैंट	पिछड़ी श्रेणी
45	चंगा राम	गांव व डा० गेहलव, फरीदाबाद	–उपरोक्त–.	––उपरोक्त–

46	प्रेम सिंह	गांव व डा० गोहाना, बुलन्द शहर (यू० पी०)	–उपरोक्त–.	––उपरोक्त–
47	सन्तोष कुमार	गांव व डा० मछियाना,बुजुरग दियोरिया (यू ० पी ०)	–उपरोक्त–.	––उपरोक्त–
48	सन्तान यादव	गांव व डा० बंछौरी, बोहरा, दियोरिया (यू ० पी०)	आयलमैन	––उपरोक्त–
49	ऊमा शकर	गांव व डा० कनुजा गोपाल गंज (बिहार)	––उपरोक्त––	––उपरोक्त–
50	रामजी यादव	गांव व डा० मेहररावा, दियोरिया (यू० पी०)	लैब बुआए	––उपरोक्त–
51	मोइनराज घर	गांव व डा० बंधरुआ, दियोरिया (यू० पी०)	आयलवर फीटरमेट	––उपरोक्त–
52	ऊमा शंकर	गाव व डा० जसोलिया, दियोरिया	सैन्टीफियुगल	––उपरोक्त–

		(यू ० पी०)	आप्रेटर	
53	बुद्ध राम	गांव व डा० खपुरी, सुरावारी, सिवन (बिहार)	–उपरोक्त––	––उपरोक्त–
54	शंकर लाल	गांव व डा० चरणवास, जयपुर (राजस्थान)	–उपरोक्त––	––उपरोक्त–
55	प्रेम नाथ.	गांव व डा० सुरिया, दियोरिया (यू० पी०)	–उपरोक्त––	––उपरोक्त–
56	कली राम	गांव व डा ० सहीनफुर सहारनपुर दिथोरिया (यू ० पी ०)	सैंटीफयुगल आप्रेटर	पिछड़ी श्रेणी
57	केहर सिंह	गांव व डा ० खरैला, गुड़गांव	वे ब्रिज फीटर	अनुसूचित जाति
58	जग नारायण	गांव व डा ० बिन्दुसार, सिवन (बिहार)	फीटर	पिछड़ी श्रेणी

59	राम करन	गांव व डा ० पतराहट, दियोरिया (यू० पी ०)	––उपरोक्त––	–उपरोक्त–
60	रणवीर सिंह	गांव व डा ० सुनहेरी कलां, रोहतक	––उपरोक्त––	–उपरोक्त–
61	छंगुर	गांव व डा ० रितारी, गोरखपुर (यू ० पी ०)	––उपरोक्त––	अनु सूचित जाति
62	शाम राय	गांव व डा ० मदीना, भुजौर, दियोरिया (यू ० पी ०)	––उपरोक्त––	पिछड़ी श्रेणी
63	आनन्द प्रकाश	गांव व डा ० बमनहेरी, मुजफर नगर (यू ० पी ०)	––उपरोक्त––	––उपरोक्त––
64	गोपाल लाल सैनी	गांव व डा ० रामचन्द्र पुर, कोटा (राजस्थान)	इलैक्ट्रिशियन	पिछड़ी श्रेणी
65	बिरेन्द्र कुमार	गांव व डा ० बामणी खेड़ा, पलवल, फरीदाबाद	वायरमैन	––उपरोक्त–

66	ललन यादव	गांव व डा ० चौरावारी, दियोरिया, (यू० पी०)	केन अनलोडर	––उपरोक्त–
67	श्रीनाथ प्रसाद	गांव व डा ० पारसिया, दियोरिया (यू ० पी ०)	हैड खलासी	अनुसूचित जाति
68	ग्यासी राम	गांव व डा० किशनगढ़, पलवल फरीदाबाद	लोहार	पिछडी जाति
69	देवदत्त	गांव व डा० होडल फरीदाबाद	बढ़ई	–उपरोक्त––
70	केदार यादव	गांव व डा० मिसरौली, दियोरिया (यू०पी०)	वैल्डर	–उपरोक्त––
71	नेमचन्द	गांव व डा० सालगढ़, पलवल, फरीदाबाद	–उपरोक्त––	–उपरोक्त––
72	गौतम कुमार	गांव व डा० बिजौली,छप्परा(बिहार)	फीटर	–उपरोक्त––

73	राम जन्म	गांव व डा० सानी संकरा,सिबन (बिहार)	पैनमैन	–उपरोक्त––
74	बिनोद प्रशाद	गांव व डा० खानपुर, दियोरिया, (यू०पी०)	सहायक पैनमैन	–उपरोक्त––
75	रामानन्द सिंह	नाव व डा9 समराबुजुंग,सिबन (बिहार)	––उपरोक्त––	–उपरोक्त––
76	रत्नसिंह	गांव व डा० नगनकलां,सोनीपत	क्याड मेट	अनुसूचित जाति
77	रामबलि	गांव व डा० सीरीरामपुर, दियोरिया (यू०पी०)	सी० फ० मेट	पिछड़ी श्रेणी
78	सुदामा प्रशाद	मांद व डा० बमरुआ, दियोरिया (यू०पी०)	–उपरोक्त–	उपरोक्त–
79	हीरा लाल	गांव व डा० माथीना बुर्जुग, (यू० पी०)	डोर मेट	उपरोक्त–

80	राम नरेश	गांव व डा० बलौरी, गोरखपुर, (यू ० पी ०)	हैडफीटर	पिछड़ी श्रेणी
81	शिव चरण	गांव व डा० सु जाती, मरेठ (यू ० पौ ०)	ब्यालर अटैन्डैन्ट	अनूसूचित जाति
82	शिव वचन	गांव व डा ० विधान, दियोरिया (यू ० पी ०)	जूस सप्लायर	–उपरोक्त–
83	दिले राम'	गांव व डा ० होडल, फरीदाबाद	केन कलर्क	––उपरोक्त–
84	सुख राम	गांव व डा ० कासीपुर धौलेगढ़, पलवल	केन कलर्क	–उपरोक्त––
85				अभुसूचित जातियां 38
				पिछड़ी श्रेणियां 46

				अनुसूचित जन–जातियां –
				जोड 84
	सर्वश्री–	वर्ष 1985– 86		
1	नवाब खान	गांव व डाकखाना पिगंवा, गुड़गाव	मजदूर	पिछडी जाति
2	धर्मवीर	गांव व डाकखाना नादीका, पलवल, फरीदाबाद	मजदूर	पिछडी जाति
3	राजिन्द्र प्रशाद	गांव व डाकखाना कुंढल, हथीन, फरीदाबाद	मजदूर	पिछडी जाति
4	सुखराम	गांव व डाकखाना बामनीखेड़ा, पलवल, फरीदाबाद	मजदूर	पिछड़ी जाति
5	गुलाब सिंह	–उपरोक्त–	मजदूर	पिछड़ी जाति

6	धर्मवीर	गांव व डाकखाना फुलवारी, पलवल, फरीदाबाद	मजदूर	पिछड़ी जाति
7	हीरा लाभ	गांव व डाकखाना हसनपुर, फरीदाबाद	मजदूर	पिछड़ी जाति
8	मुलचन्द	गांव व डाकखाना फुलवारी, असबटा, फरीदाबाद	कुली	अनुसूचित जाति
9	रतन	–उपरोक्त–	कुली	अनुसूचित जाति
10	दीराज	–उपरोक्त–	कुली	अनुसूचित जाति
11	उधेराम	–उपरोक्त–	कुली	अनुसूचित जाति
12	सलगी	–उपरोक्त–	कुली	अनुसूचित जाति
13	राजकुमार	–उपरोक्त–	कुली	अनुसूचित जाति
14	राजवीर	–उपरोक्त–	कुली	अनुसूचित जाति

15	तेजराम	गांव व डाकखाना पिमगोरे, पलवल, फरीदाबाद	कुली	अनुसूचित जाति
16	सोम प्रकाश	गांव व डाकखाना वलीपाखेड़ी, सहारनपुर (यू० पी ०)	खलासी	पिछड़ा जाति
17	कालू राम	गांव व डाकखाना नवासी पुरवा, बाराबंकी (यू० पी ०)	खलासी	पिछड़ा जाति
18	बरीगू नाथ	गांव व डाकखाना मसरौली, दियोरिया (यू० पी०)	खलासी	पिछड़ा जाति
19	राम आणरम	गांव व डाकखाना बसीपुर, देयोरिया (यू० पी०)	मोटर अटैन्डैन्ट	पिछड़ा जाति
20	राम अवध भणत	गांव व डाकखाना छापीया, बागुरुआ (यू० पी०)	ओ० एफ० मेट	पिछड़ा जाति
21	ओमप्रकाश	गांव व डाकखाना रसोती, सवाई,	मैसन	पिछड़ा जाति

		माधोपुर (राजस्थान)		
22	स्याम लाल	गांव व डाकखाना भुलवाना, होडल, फरीदाबाद	मैसन डोर मैट	अनुसूचित जनजाति
23	राम अवध यादव	गाय व डाकखाना पकड़ी बुजुरग, दियोरिया (यू० पी०)		पिछड़ा जाति
				अनुसूचित जाति 9
				अनुसूचित जनजाति –
				पिछ्डी जाति 14
				जोड़ : 23

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, मैंने पूछा था कि पलवल, पानीपत और करनाल में कितनी लकड़ी खरीदी गई? स्टेटमैंट को देखने से पता चलता है कि पलवल में करनाल के मुकाबले में चार गुणा ज्यादा लकड़ी खरीदी गई और सात गुणा कम शूगरकेन पीड़ा गया । इसी तरह से पानीपत से डेढ़ गुणा ज्यादा लकड़ी ली गई और पांच गुणा कम शूगर प्रोड्यूस हुई? क्या मन्दी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है?

श्री प्यारा सिंह : स्पीकर साहब, पानीपत और करनाल की मिल्ज पुरानी हैं । जो नई मिल होती है उसका ब्यालर गर्म करने के लिए ज्यादा लकड़ी प्रयोग करनी पड़ती है ।

चौधरी अकमत खां : स्पीकर साहब, चार्ट को जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि वर्ष 1985–88 मे पलवल में 24412 क्विटल्ज लकड़ी खरीदी गई और 4.45 क्यिंटल्ज गन्ना पेड़ा गया । पानीपत में 14504 क्विंटल्ज लकड़ी खरीदी गई और 13.06 क्विंटल्ज गन्ना पेड़ा गया । करनाल में 7490 क्यिंटल्ज लकड़ी खरीदी गई और 15.56 क्विटल्ज गन्ना पेड़ा गया । नई मिल होने के मारे में पिछले साल की बात तो मानी जा सकती है लेंकिन इस साल यह डिफरैन्स क्यो है

श्री प्यारा सिंह : स्पीकर साहब, पिछले साल भी यह क्वैश्चन आया था । पिछले साल आठ लाख की लकड़ी अली थी और हमने उसकी इंक्वायरी कराई थी । 1985–86 में 12 लाल 52

हजार 248 रुपए की लकड़ी जली है और इसकी इक्वायरी हम कराने जा के हैं ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, पिछले साल भी मैंने यह क्वैश्चन पूछा था । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो लकड़ी परचेज की गई यह प्राईवेट ऐजेन्सी से खरीदी गई या फोरैस्ट डिपार्टमैंट से ली गई क्योंकि सरकार ने सारा लकडी का काम अपने हाथ में लिया हुआ है?

श्री प्यारा सिंह : स्पीकर साहब, 30— 10— 1984 को लकड़ी के लिए अखबारों में एडवरटाइजमैंट की थी और मिल वालों ने महकमा जंगलात वालों का टैन्डर मन्जूर किया और अठारह हजार रुपया उनको पेशगी दे दिया । उन्होंने हमें बहुत थोड़ी लकड़ी दी । जब उन्होने हमें लकड़ी नहीं दी तो हमने दुबारा इस बारे मे पूछा । उसके बाद कुछ और पार्टीज आई और कहा कि हमसे लकडी ले लो । हमने लोकत पेटी सप्लायर से 250 क्यिंटल लकड़ी ले ली, वन विभाग से 2978 क्विंटल ली और मैसर्ज हबर कान्ट्रैक्टर से 4405 क्विंटल लकडी ले ली । जंगलात विभाग के जितने डिप्रोज हैं उनमें हमारे आदमी जाते रहे हैं लेकिन उन्होंने लकड़ी देने सै इन्कार किया ।

10.00 बजे ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि जो लफडा खरीदी गयी

थी, वह किस किस्म की थी? शीशम की थी, किकर की थी यहू और किस्म की थी और उनका अलग अलग क्या रेट था?

श्री प्यारा सिंह : स्पीकर साहब, शीशम, किकर, सूखी–गिली, मिली–जुली व डी हमने खरीदी थी लेकिन उनका भाव अलग अलग था 1 किसी का 44, किसी का 50 व किसी का 60 रुपये क्यिंटल था ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने रिप्लाई के अनैक्सचर (सी) में पलवल सहकारी चीनी मिल में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या बतायी है और 1984–85 की भर्ती के मुकाबले में 1985– 86 में भर्ती कम की गयी है जबकि यह क्लेम करते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है । मैं आपके बजरिया यह जानना चाहता हूं कि यह भर्ती कम क्यों कर दी गयी है 7–

श्री प्यारा सिंह : स्पीकर साहब, लकड़ी से सम्बन्धित सवाल ही काफी लम्बा चौडा है । पहले इस बारे में तो सारी जानकारी प्राप्त कर लें । भर्ती के बारे में याद में बता देंगे ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने वताया कि शूगर मिलो की मशीनरी काफी पुरानी है जिसकी वजह से लकड़ी की खपत काफी होती है । सरकार क्यों नहीं पुरानी मशीनरी को बदल देती ताकि लकडी की खपत कम हो ।

क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री प्यारा सिंह : स्पीकर साहब, मैंने यह नही कहा कि मशीनरी पुरानी चौधरी अजमत खां स्पीकर साहब, लकड़ी के बारे में जो मिनिस्टर साहब ने व्यान दिया है, क्या मन्त्री महोदय स्वयं उससे सन्तुष्ट हैं कि यह सही है ? मैं आपके जरिये मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो लकड़ी खरीदी गई है, उसमें काफी घपला हुआ है और जो मिलें लोगों की भलाई के लिये थीं, उनमें नुक्सान होना शुरू हो गया है, क्या हरियाणा की गरीब जनता के ऊपर यह एक किस्म का बर्डन सा है? क्या इसकी जांच करवाएंगे? दूसरी बात यह कि जो भर्ती की गयी है वह यू ० पी ०, बिहार और राजस्थान से, साथ लगती स्टेटों से की गयी है? क्या सरकार को हरियाणा से कोई आदमी नहीं मिल रहे थे? क्या इस बात की जांच करवाई जाएगी कि ऐसा क्यों है?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, सभी मिलों में ऐसा ही हाल है । शाहबाद में भी यू ० पी ० के लोग ज्यादा हैं ।

श्री प्यारा सिंह : स्पीकर सर, सरकार सभी बातों को काफी गौर से एग्जामिन करवा रही है । जहां तक भर्ती का सवाल है, वहां के आदमी ज्यादा टेक्नीकल होते है इसलिये कुछ भर्ती बाहर से की गयी है ।

श्री जगदीश चेहरा : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने जितने भी सवालों के जवाब दिये हैं, हमारी समझ में तो कोई आया नहीं फिर भी सन्तोष कर रहे हैं । मैं आपके जरिये मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर और शूगर मिल लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री प्यारा सिंह : ऐसा सवाल कल की लिस्ट में आ रहा है, उस वक्त जवाब दे दूंगा ।

चौधरी तैयब हुसैन : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब के जवाब के अनैक्सचर, यू, बी, सी, को देखने से पता चलता है कि लकड़ी की खपत तो ज्यादा हुई है लेकिन गन्ने की क्रशिंग कम हुई है । यह सीधा ही प्राइमा–फेशिया केस बनता है । क्या इस कारे में कोई कार्य वाही की जा रही है, इसकी जांच पड़ताल कहां तक पहुंच चुकी है और क्या सरकार ने अब तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया है ? केस किन स्टेज पर है और कौन अफसर इसकी इंक्वायरी कर रहा है?

श्री प्यारा सिंह : स्पीकर साहब, मैनेजिंग डायरैक्टर, शूगर मिल्ज फैडरेशन इसकी जांच कर रहा है । पहले कों इक्वायरी करवायी गयी थी उस से हमें तसल्ली नहीं है । सारी बातें सरकार के विचाराधीन हैं ।

Reduction in rate of Sales Tax on Bi-Cycles

***1193. Seth Ram Dass Dhamija :** Will the Minister

for industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the existing rate of Sales Tax on the sale of Bi-Cycle in the State ; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to materialise ?

उद्योग मन्त्री (श्री श्रीकिशन दास) :

(क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, हमारी स्टेट में दूसरी स्टेटों की निस्बत साईकल पूर सेलज टैक्स है और वह लगभग 10 परसैन्ट लिया जाता है । 20 सूत्री कार्यकम अनुसार यह टैक्स गरीब आदमियों पर ही पड़ता है जबकि कारों पर सेल्ज टैक्स कम है। क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई प्रोपोजल है जिससे इस टैक्स को माफ किया जा सके या कम किया जा सके ताकि गरीब –लोगों को कुछ राहत महसूस हो?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, 8 परसैन्ट सेल्ज टैक्स है और 2 परसैन्ट चार्ज है जिससे हमको लगभग 1 करोड़ रुपया सालाना आमदनी होती है । जो माल बाहर है उस पर हम दो परसैन्ट सर चार्ज लेते हैं और साथ में (सी) फार्म भी

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि चुकि ट्रैक्टर पर टैक्स नहीं है तो क्या साईकल पर टैक्स हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार चूंकि आदमी साईकल खरीदते हैं, इसलिये इस पर टैक्स नहीं होना चाहिये । क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर ध्यान देगी जिससे गरीब लोगों का उत्थान हो सके?

श्री श्रीकिशन दास : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता है सरकार का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, हरियाणा में बनने वाला साईकल विदेशों में भी पापुलर है । क्या सरकार एक्सपोर्ट अधिक से अधिक बढ़ाने का विचार रखती क्या सरकार इस तरह का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सामने रखने का विचार कर रही है?

श्री श्रीकिशन, दास : अभी सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । डायरैक्ट रिपोर्ट पर पहले ही कोई कर नहीं है ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता है यह जो हमारा सेल्ज टैक्स का स्ट्रकचर है, क्या इसको सरल बनाने का कोई तरीका है जिससे हमारे व्यापारी भाइयों का भारी वजन दूर हो सके और टैक्स

विजन भी दूर हो सके तथा सरकार की भी रोजमर्रा की परेशानी दूर हो सके?

श्री श्रीकिशन दास : अगर डा ० साहब इस बारे में कोई प्रोपोजल देंगे तो उसको लिया जाएगा ।

Setting up of a Primary Health Centre at Village Gangana in District Sonepat

***1165. Shri Bhalle Ram :** Will the Minister for Health be pleased ;tate —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Primary Health Centre at Village Gangana in District Sonepat ; and

(b) if so. the time by which the said centre is likely to be set up?

Health Minister (Shri Goverdhan Dass Chauhan) :

(a) No.

(b) In view of (a) above question does not arise.

श्री भले राम : स्पीकर साहब, पिछले साल मार्च में जो बजट पास हुआ उसमें यह मैन्शन था कि पांच साला प्लान में हरियाणा सरकार 150 पी ० ए० सीज० बनाएगी जिदमें से 31 प्राइमरी हैल्प सैन्टर्ज बन गए हैं । उसमें यह भी कि जिस गांव की पापुलेशन तीस हजार होगी, वहां यह सैन्टर बनेगा । इस बारे मैंने

पंचायत का प्रस्ताव भी भेजा है और चीफ मिनिस्टर साहब को एक नोट कर भी दिया था । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हू कि मन्त्री जी ने मेरे उस को एग्जामिन करके जवाब 'नो' में दिया है या वैसे ही दिया है?

श्री गोवर्धन दास चौहान : जिस गांव की ये बात कर रहे हैं, उसके 4– 5 किलो मीटर पर एक सिवानामाल गांव है, उसमे प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोल दिया है । इसके साथ तीस हजार की आबादी भी पड़ती थी । फिर भी इनके नोट को हम कोशिश कर रहे हैं । अगर गांव वाले चार एकड़ जमीन और पांच कमरे बना कर दे तो हम वहां भी खोल देंगे ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न सोनीपत जिले है लेकिन आपकी लिब्रल एप्रोच को ध्यान में रखते हुए और लायक मन्त्री के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आशा करुंगा कि मैं जो सवाल पुछूंगा वे उत्तर दे पाएंगे । मेरे हल्के बरवाला में 28 जनवरी, 1986 को एक साल हैल्थ सैन्टर सैंकशन हुआ था उस बारे में मैंने मन्दी जी को कई बार जबानी भी की है और लिख कर भी दिया है कि उसे जल्दी चालू करवाएं । हसनगढ मेरा अपना गांव णै, वहां भी 2 8– 1–86 को प्राइमरी हैल्थ सैन्टर से हुआ था, उसको भी जल्दी चालू करवाने की कोशिश करें । तीसरे मिरजपुर गांव बड़ा है और उसकी आबादी तीस हजार की है । वहां पर बहुत पुराना से हैल्थ सैन्टर है लेकिन उसकी चार दीवारी भी नहीं है । वहां की जमीन पर ने

नाजायज कब्जा कर रखा है, क्या उस नाजायज कव्वे को छुडवाएंगे?

श्री गोवर्धन दास चौहान : स्पीकर साहब, हसनगढ में हम जल्दी ही प्रान्त मे हैल्थ सैन्टर चालू कर देंगे । जहां तक बरवाला की बात है, इसको एग्जामिन करवायेगें लोगे ने जो मिरजपुर में नाजायज कब्जा किया हुआ है, उसको जल्दी खाली कर देंगे और उर्सके बाद चार दीवारी बनाने की भी कोशिश करेंगे?

श्री भले राम : स्पीकर साहब, इस साल कुछ सबसिडी हैल्थ सैन्टर से प्रान्त हैल्थ सैन्टर अपग्रेड हुए हैं । मेरे हल्के के गांव बुटाना में भी अपग्रेड हुआ है लेकिन यहां पर अभी स्टाफ नहीं पहुंचा है । क्या स्टाफ सैंकशन हो गया है या अभी कोई

श्री गोवर्धन बास चौहान : स्टाफ अभी सैंकशन होकर आना है । जैसे ही सैकशन आ जाएगी, हम स्टाफ भेज देंगे ।

Construction of Dams to control flow of Rainy Water

***1177. Shri Jagdish Nehra :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration. of the Government to construct Dams to control rainy water from flowing out of the State during rainy season and to utilize it for providing more irrigation facilities in the State, if so, the number there of and the names of places where such Dams are to be constructed ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Yes. There is a proposal of the Government to construct four number Barrages namely (1) Hathni Kund Barrage (2) Dhanaura Barrage (3) Jaspur Barrage and (4) Massani Barrage to control rain water for productive use.

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो धग्गर का पानी बह कर राजस्थान को जाता है, क्या उसको रोक 'कर कोई डैम बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, घग्गर के पानी के लिए पहले ही ओटू में बैरेज बना हुआ है जिससे दौ नहरें भी निकाली हुई हैं यह ठीक है कि उसकी डि–सिलटिंग की जरूरत है । पिछले साल सरकार ने कुछ रुपया उसके लिए मन्जूर किया था तेकिन उस पर अगर हम कोई फरदर चेंज करेंगे तो, जो रानी इस समय हम यूटिलाइज कर रहे है, वह नही कर सकेंगे ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे यहां नलवी–शाहबाद प्रोजैक्ट बन रहा है जिस पर सैकशन 4 और 6 को कार्यवाही पार्टली कुछ हिस्सों पर हो चुकी है और शायद उस पर काम भी लगने वाला है ले किन उसके हैड का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ । यह पहली मिसाल है कि हैड का फैसला न हुआ हो और मेन चौनल के लिये जमीन एक्वायर कर ली नए और काम शुरू कर दिया जाए । हैड को छोड़ने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मेरे लिये तो यह एक खबर है कि हैड का अभी फैसला नहीं हुआ है । डा ० साहब के पास अगर एक्सक्लूसवली सूचना हो तो वे मुझे–वना दें, हम देख लेगे । वैसे यह खबर ठीक नहीं है ।

ठाकुर बहादुर सिंह : स्पीकर साहब, आज से दो साल पहले घग्गर के पानी के लिये मन्त्री जी ने तीन स्वाट्स का मुआना किया था । वे हैं ओटू लेक, मसाईवाला प्वांयट और मीरपुर प्वांयट । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या प्रोग्रैस हुई है और इस पानी को इस्तेमाल करने का क्या प्रोग्राम बनाया है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सिरसा जिले में जिन एरियाज में नहरी पानी की कमी है वहां पुराने चेनल्ज को आगमैट करने के लिये दो तीन जगहों से पानी लिफट करके कुछ नहरों को पानी देने की योजना थी, वह सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ़ जिले में पानी कम पहुंचता है क्योकि वह टेल पर है । वहां आखिर तक पानी नहीं पहुंचता । मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि वहां पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था कब तक कर दो जाएगो?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, अगर इनका मुद्दा जे ० एल० एन ० कैनाल से है तो अभी उस नहर में पूरा पानी नही चल सकता । जब एम० वाई ० एल० नहर का पानी

आएगा तो वह उसमें डाल देंगे । उसके वाद ही सारा साल पूरा पानी जाने का प्रोग्राम वन सकेगा । अभी हम साल में कुछ दिनों के लिए उसमें जमना को पानी देन का प्रयत्न करते हैं जोकि मैं मानता हूं कि वह सभी जगह नही पहुंच सकता ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, मैं पहले भी कई दफा सरकार के नोटिस में ला चुका हूं कि अम्बाला जिले में कालका ओर छछरौली जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर छोटे–छोटे डैम बनाए जा सकते हैं । वहां पर कुछ डैम बने हुए भी हैं । लेकिन उन इलाकों मे महकमा इरीगेशन ने डैम बनाने की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी है । जे। डैम वनाए गए हुँ, वे महकमा एग्रीकल्चर और महकमा फारैस्ट ने मिल कर बनाए हुए हैं । यदि महकमा इरीगेशन इन दोनों महकमों यानी महकमा एग्रीकल्चर और महकमा फारैस्ट को डैम बनाने के लिये फण्डज अलाट कर दे तो वहां पर बहुत से छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी सै जानना चाहूंगा कि क्या सरकार महकमा एग्रीकल्चर और महकमा फारैस्ट को पहाडी इलाकों में डैम बनाने के लिये फण्डज अलाट करेगी ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, अम्बाला जिला कान्डी एरिया है । इसलिये उस एरिया में 858 छोटे छोटे बांध बनाने का सरकार का प्रोग्राम है । इस काम के लिये महकमा फाइनैन्स फण्ड अलाट करता है । इरीगेशन डिपार्टमैंट कोई फण्ड अलाट नही करता । कालका के इलाके में

छोटे छोटे 209 बांध वनने हैं, उन पर लगभग 10.26 करोड़ रुपए खर्च होंगे । नारायणगढ़ के इलाके में 476 छोटे छोटे बाध बनने हैं जिन पर लगभग 16.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसी तरह से जगाधरी के इलाके में 173 छोटे–छोटे बांध बनने है जिन पर लगभग 6. 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे । यह काम इरीगेशन डिपार्टमैंट ने नहीं करना है महकमा जंगलात और महकमा एग्रीकल्चर मिल कर इस काम को करेंगे ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह काम कितने दिनों में पूरा हो जायेगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : यह काम इरीगेशन महकमे ने नहीं करना है । पीरियड के बारे में इस समय मेरे पास कोई इन्फर्मेशन नहीं है कि कितने दिनों में काम पूरा होगा । अगर माननीय सदस्य इस बारे में सैपरेट सवाल पूछेंगे तो जवाब दे देंगे ।

High Schools/Higher Secondary Schools and Schools having 10+2 System in the State

***1188. Chaudhri Azmat Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the sub-division-wise number of High/Higher Secondary/ 10+2 system schools, separately, in the State at present;

(b) the number of posts of Headmasters lying vacant as at present in the schools, as referred to in part (a) above and

(c) the steps taken and the time by which the posts as referred to in part (b) above, are likely to be filled up ?

Education Minister (Shrimati Sharda Rani) :

(a) The sub-division-wise number of High/10+2 system schools is given at Annexure-I. With the switch-over to 10+2 system of education, there is no Higher Secondary School in Haryana.

(b) At present about 45 posts of Headmasters are lying vacant.

(c) Efforts are being made to fill up the vacant posts of Headmasters as early as possible.

ANNEXURE—A

List of Government Senior Secondary Schools & High Schools in November, 1986

	Sub-Division	No. of Sr. Sec. Schools	No. of High Schools
1.	Ambala	3	51
2.	Jagadhari	4	43
3.	Naraingarh	1	31

4.	Panchkula	2	16
5.	Bhiwani	4	57
6:'	Charkhi Charkhi Dadri	5	42
7.	Loharu	4	35
8.	Ballabgarh	6	52
9.	Palwal	5	61
10.	Gurgaon	6	59
11.	Nuh	2	16
12.	Ferozepur Zhirka	2	24
13.	Hissar	7	93
14.	Hansi	5	46
15.	Fatehabad	5	43
16.	Tohana	—	22
17.	Jind	3	48
18.	Safidon	3	18
19.	Narwana	3	54
20.	Karnal	8	96
21.	Panipat	5	51
22.	Thanesar	2	51

23.	Kaithal	4	49
24.	Guhla	—	24
25.	Mahendergarh	3	36
26.	Narnaul	3	41
27.	Rewari	5	58
28.	Rohtak	7	94
29.	Bahadurgarh	5	36
30.	Jhajjar	5	74
31.	Sirsa	4	44
32.	Dabwali	4	35
33.	Sonipat	4	80
34.	Gobana	3	42
	Total	132	1622

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, नूह और फिरोजपुर झिरका में सीनियर सैकेडरी स्कूल्ज तथा हाई स्कूलों की तादाद बहुत कम है जबकि दूसरी जगहों पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है । नूह में हाई स्कूलों की सख्या है और फिरोजपुर झिरका में 24 है जबकि दूसरी जगहों पर वह संख्या 80 तक भी है । मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नूह और फिरोजपुर सिरका में ज्यादा स्कूल अपग्रेड करने का सरकार का कोई विचार

है और क्या सरकार वहां पर सीनियर सैकेंडरी तथा हाई स्कूल ज्यादा खोलने पर विचार करेगी?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, अगर डिमांड होगी तो सरकार इस मांग को कंसिडर करेगी ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, हैडमास्टर्ज की सिलैक्शन लिस्ट बनी हुई है । मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हुं कि जो हैडमास्टर्ज अप्यायंट किए जाएंगे क्या वे उसी लिस्ट में से अप्यायंट किए जाएंगे?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, वह लिस्ट बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिये उस लिस्ट में से अप्वायंट नहीं किए जा सकते ।

चौधरी साहब सिंह सैनी : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने मेन सवाल के लिखित रिप्लाई में सीरियल नम्बर 22 पर थानेसर के बारे में सूचना दी है । उसमें लिखा है कि थानेसर में सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों की संख्या 2 है और हाई स्कूलों की संख्या 51 है । थानेसर सबडिविजन बहुत बड़ा है लेकिन उसमें सीनियर सैकेण्डरी स्कूल केवल 2 ही हैं जो बहुत ही कम है। हाई स्कूलों से और दूसरे गांवों से बच्चे इन दो स्कूलों में दाखिला लेने के लिए आते हैं लेकिन संख्या अधिक होने के कारण गरीब बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाता, उनको प्राइवेट कालिजों में जाना पड़ता है । मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता

हूं कि क्या थानेसर सबडिवीजन में हाई स्कूलो को सीनियर सैकेण्डरी स्कूल अपग्रेड करने का सरकार का कोई विचार है?

श्रीमती शारदा रानी : सीकर साहब, इस साल स्कूल अपग्रेड करने का कोई विचार नहीं है । बहुत ज्यादा सीनियर सैकेण्डरी स्कूल कहीं पर भी नहीं हैं ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब जगाधरी में सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की बिल्डिग' अंग्रेजों के जमाने में 1913 में बनी थी और उसका रकबा लगभग तीन एकड़ का है । आज इस जमाने के अन्दर उस स्कूल में तीन स्कूल हैं, यानी उस बिल्डिंग में सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, गवर्नमैंट गर्ल्ज हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं । इन तीनों स्कूलों का कम्पाउन्ड एक ही है । उस तीन एकड़ के रकबे में तीनों स्कूलों के बच्चे कहा पर खेल सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, उसमें बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है । शायद वहां दौ चार कमरे और बने होंगे । अब आप ही बताए उस जगह में बच्चे – कहां पर बैठ सकते हैं और खेल सकते हैं? में आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि सरकार जगाधरी. में सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की अलग बिल्डिंग बनाने के लिये जगह देने के बारे में विचार करेगी और वहां पर बिल्डिंग बनाई जाएगी?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, अगर वहां के नागरिक और नगरपालिका हमें सहयोग दे तथा हमारे पास फण्डज अवेलेबल होंगे तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, हैडमास्टर्ज की अप्वायटमैंट के बारे में तो मन्त्री महोदया ने जवाब दे दिया है, लेकिन जो हिली एरियाज हैं, जैसे मोरनी हिल्ज, कालका और कई छोटी छोटी जगहें हैं, वहां के प्राइमरी स्कूलों में टीचर्ज नहीं हैं । मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी जगहों पर प्राइमरी स्कूलों में जल्दी ही टीचर्ज भेजने का इन्तजाम करेगी?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, हम तो अपनी तरफ से टीचर्ज भेजने की पूरी चेष्टा करते हैं लेकिन इनके इलाके में कोई टीचर जाने के लिये तैयार नहीं होता । इनके इलाके में टीचर जाने की बजाय नौकरी छोड़ना पसन्द करते हैं लेकिन वहां के लिये तैयार नहीं होते ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, सरकार उसी इलाके के लोगों को भर्ती क्यों नहीं करती? वहीं के लोकल आदमियो को भी लगाया जा सकता है?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, यदि उसी इलाके के लोग मैरिट पर होंगे तो विचार किया जा सकता है लेकिन मैरिट पर आते ही नहीं हैं ।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय. इनके इलाके में टीचर्ज भेजने का इन्तजाम करेंगे ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, बहुत से गाव ऐसे हैं जहां हाई स्कूल के लिए 20–20 और 25– 25 कमरे बनाए हुए हैं । लोगों ने लाखों रुपए चन्दे के इकट्ठे करदे. बिल्डिग वनाई हुई है और उन स्कूलो को अपग्रेड करने का पूरा क्राइटेरिया भी सकता है । यह बात भी ठीक है कि हरियाणा सरकार काफी स्कूलों को अपग्रेड कर चुकी है लेकिन इस समय भी गांव वालों ने बहुत से गांवों में बिल्डिगें बना रखी हैं। मेरे हल्के के अन्दर मदीना गाव में एक बिल्डिंग मे 27 कमरे बनाए हुए हैं । मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया मे जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर उस स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा ?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, इस साल सरकार का स्कूल अपग्रेड करने का कोई विचार नही है । अगले सात्र इस पर विचार कर लेंगे ।

चौधरी अबमत खां : स्पीकर साहब, पहले तो स्कूल कम होते थे और उनमें हैड मास्टर्ज और जे ० बी ० टी ० टीचर्ज नहीं होते थे । मेवात में जितने स्कूल हैं, उनके अन्दर कम से कम 700 टीचर्ज की जरूरत होगी लेकिन वहां पर केवल 200 टीचर हुँ जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है । दूसरी तरफ रोहतक और सोनीपत में बहुत ज्यादा मात्रा में टीचर्ज हैं । मैं आपके द्वारा

मन्की महोदया से जानना चाहता हूं कि यदि मेवात के इलाके में टीचर्ज जाना नहीं चाहते, जैसे अभी इन्होंने खुद बताया था कि ऐसे इलाकों में टीचर्ज जाना पसन्द नहीं करते, तो क्या उसी इलाके के टीचर्ज को ट्रेनिंग दे कर वहीं पर लगाया जाएगा? वहां पर ट्रेनिंग स्कूल खोल कर वहीं के लोगों को ट्रेनिंग देकर लगाया जा सकता है । क्या इस बारे में विचार किया जा सकता है?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, हम इस सुझाव पर विचार कर लेंगे ।

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं हैं और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल की ब्रांचिज चल रही हैं । मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं, क्या वहां प्राइमरी स्कूल खोलने की सरकार की कोई योजना है, और जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल की ब्रांचिज चलं रही हैं, क्या उन ब्रांचिज को रैगलर प्राइमरी स्कूल बनाया जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, वैसे तो यह सवाल हाई स्कूल और सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के बारे में है, लेकिन फिर भी मैं प्राइमरी स्कूलों के बारे में. बता देती हूं । जिस ब्रांच में बच्चे पूरे हों, उसको प्राइमरी स्कूल बनाया जा सकता है लेकिन साथ में बिल्डिंग भी पूरी होनी चाहिए ।

श्री अमीर चन्द मक्कड : स्पीकर साहब, हांसी में सीनियर सैकेण्डरी स्कूल पिछले कई सालों से बना हुआ है लेकिन उसकी बिल्डिंग अनसेफ डिकलेयर की हुई है । वहां पर नई बिल्डिंग बनाने के लिए छह लाख रुपए का एस्टीमेट भी पास हो चुका हैं । मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि उस बिल्डिंग को कब तक बनाने का सरकार का विचार शै?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, इस बारे में जांच करवा लेंगे । इस समय मेरे पास यह इन्फर्मेशन नहीं है कि वहां पर क्या स्थिति है ।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Abolition of land revenue

***1194. Seth Ram Bass Dhamija :** Will the Minister of State for Revenue be pleased to state whether any decision has been taken by the Government to abolish land revenue in the State; if so, the extent of benefit likely to be accrued to the beneficiaries alongwith the number thereof ?

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Yes, Sir. 5,74,970 beneficiaries have been benefitted to the extent of Rs. 322 lakhs every year.

विभिन्न विषयो का उठाया जाना

(1) तहसील कालका के गांव सकेतड़ी में जंगली सूअरों द्वारा फसल नष्ट करने सम्बन्धी

श्री लछमन सिह : स्पीकर साहब, मैं सरकार के नोटिस में एक बहुत जरूरी सूचना देना चाहूंगा । मेरे हल्के में एक सकेतड़ी गांव है । वहां सकेतड़ी के नजदीक एक फोरैस्ट है । वह फोरैस्ट यू० टी० के अन्दर आता है । वहां पर यू ० टी ० वालों ने एक बर्ड सैंकच्यूरी बनाई हुई है । उसके अन्दर वाईल्ड बोर –बहुत ज्यादा हैं । चण्डीगढ़ में वे लेक के अन्दर पानी पीने के लिये आते हैं और सकेतड़ी के आसपास के गांवों में हरियाणा की तमाम फसल तबाह कर देते हैं । यू ० टी० वाले तो उन्हें कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि उनकी तो वहां पर सैंकच्यूरी है । यह एक इन्टर स्टेट मैटर है । जब वाईल्ड बोर गांव के खेतों में आ जाते हैं तो वहां भी हरियाणा सरकार की तरफ से उनको मारने की पाबन्दी है। इसलिये या तो सरकार यह इजाजत दे कि जो वाईल्ड बोर है, यानी जो जंगली सूअर है, जब वे किसानों के खेतों में आयें तो उनको किसान मार सके । यदि ऐसा नहीं कर सकते तो किसानों को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि किसानों की फसलों को बहुत लौस हो रहा है । सकेतड़ी यू० टी ० के बौर्डर पर है, सिर्फ एक डेढ़ किलोमीटर के फासले पर ही है । स्पीकर साहब, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगा कि लोगों ने जंगली सूअरों से अपनी फसलों को बचाने के लिये खेतों में ऊंचे ऊबे मचान बनाये हुए हैं । वे सारी सारी रात

डोल बजा कर अपनी फसलों को तबाह होने से बचाते हैं । ढोल बजाने पर भी जंगलात का जो वाईल्ड लाईफ डिपार्टमैंट है, वह एतराज करता हैं । वह कहते हैं कि आप ढोल की आवाज में कहीं गोली न चला दें और किसी जानवर को न मार दें । यह किसानों की बड़ी भारी समस्या है । इससे एग्रीकल्चर को भी लौस है । इस तरफ सरकार को फौरी तौर पर ध्यान देना चाहिए । यू० टी० वाले तो कहते हैं कि हम उनको कैसे रोकें क्योंकि वे पानी पाने के लिये लेक में आएंगे । वहां पर ऐसे जानवर बहुत ज्यादा हैं । वे यू ० टी० का माल खा रहे हैं और पल रहे हैं लेकिन नुकसान हरियाणा के किसानों का हो रहा है । इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करुंगा कि यह बहुत भारी समस्या है, इसका जल्दी से जल्दी कोई न कोई प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिए । मेरा सुझाव हैं कि सरकार उन जमीदारों को, जब वे जानवर उनकी फसल में जायें तो मारने की इजाजत दे । It is controlled by the Union Territory Chandigarh. जब पंजाब का फैसला होने वाला था तो यह इलाका हरियाणा को ट्रांस्फर होना था । It would have come to Haryana. जब तक वह एरिया यू० टी० में है, तब तक उसके लिये कोई न कोई सरकार को फौरी तौर पर प्रबन्ध करना चाहिए क्योंकि वहा पर किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और वे जमींदार इन जानवरों से काफी परेशान हैं ।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : यह बात ठीक है । मुझे भी कई डैपूटेशन इस सिल– सिले में मिले हैं । हम भारत

सरकार के साथ इस मैटर को टेक–अप करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल कर सकें ।

(2) रंगोई नाले में अवरोध के कारण आने वाली बाद से हुई क्षति सम्बन्धी

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, हमारे फतेहाबाद सब डिवीजन में हर दूसरे साल इतना जब्रदस्त फल्ड आता है जिसका कोई हिसाब नहीं । हमारे यहां एक रंगोई नाला है जो हैवक क्रिएट करता है । वह 100 साल पुराना है । उससे पानी निकाल कर ओटू झील मै डाला जाता था । अब मेरे पास डैफिनेट इन्फर्मेशन है कि रिहैबलीटेशन डिपार्टमैंट वाले उस नाले की कुछ जमीन को सेल कर रहे हैं । पिछले फल्ड में भी वहां पर बहुत तबाही हुई थी । इस बारे में मैं अर्ज करूंगा कि उसको एक सही नाले का रूप दिया जाये ताकि फतेहाबाद को बचाया जा सके । यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो हर दो साल बाद वहां पर फल्ड आता हे उससे– वहां के गरीब लोगों के मकान और झोपड़ियों को काफी नुकसान पहुंचता बै । वे सभी तबाह हो जाते हैं । इस बारे में मैं सरकार से रिबैस्ट करूंगा कि रंगोई नाले को जो हमारी लाईफ लाईन है, नाले का रूप दिया जाये और अगर वहां पर जमीन सेल हो रही हो तो उसको भी रोका जाये ताकि पानी की निकासी हो सके।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, उस इलाके की फल्ड की बात तो माननीय सदस्य ने पहले कभी नहीं बताई । अगर ये इस बारे में पूरी तफसील देंगे तो पता कर लेंगे कि कौन सी जगह फल्ड आता है । आया यह फल्ड खेतों में आता है या शहरों या गांवों में आता है । जहां तक जमीन को बेचने न सवाल है उसके बारे में मैं समझता हूं कि पूरो इन्फर्मेशन इनके पास नहीं है । अगर है तो वह पता कर लें कि कौन से डिपार्टमैंट की जमीन है और उस जमीन को कौन बेच रहा है । जब पूरी इन्फर्मेशन हमारे पास आ जायेगी तो इनकी समस्या का जो भी समाधान होगा, वह करेंगे ।

(3) नील गाय द्वारा नष्ट की गई फसलों सम्बन्धी

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, हांसी एरिया में महाराजा फरीदकोट का एक जंगलात का काफी एरिया पड़ा है जिसमें नील गाय काफी तादाद में रहती हैं । ये गाये आस पास की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाती है । इस बारे में हर सैशन में सवाल आते रहते हैं । लीग भी धार्मिक भावनाओं की वजह से इन नील गायों को मारते नही है । वह जंगलात ऐसे ही पड़ा हुआ है । इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि अगर उस जमीन को एक्वायर करके छोटे छोटे किसानों में बांट दें तो एकु तो वहां पर खेती हो जाएगी और दूसरे लोगो का नील गायों से पीछा छूट जायेगा ।

चौधरी बिलु राम बाजीगर : स्नीकर साहब, मेरे हल्के की दो तीन प्रौब्लम्ज ऐसी हैं जिनके बारे मे मैं मन्त्री जी से कई दफा मिला हूं । घग्गर नदी में जव फल्ड आ जाता है तो 14–15 गांवों की फसल डूब जाती है । अगर कुछ बचती हैं तो उस पर नहरी मामला लगता है । इस बारे में मैं मन्द्री महोदय से कई बार मिला लेकिन अभी तक समस्या ज्यो की त्यों है । आज भी 15–20 लोग मेरी कोठी पर आए हुए हैं । अगर मन्त्री महोदय टाईम दें तो मैं उन्हें इन्हें मिला भी दूंगा । ये मामला स्टे कर दौ है लेकिन उससे समस्या हल नहीं होती । इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करुंगा लिए इस मसले को किसी न किसी तरह से जड़ से उखाड़ा जाए । दूसरी बात, स्पीकर साहब, यह है कि मेरे हल्के में कई मीलों तक जंगल फैलों हुआ है । उसने नील गायें इतनी है जिसका कोई हिसाब नही । उन्हें कोई मार नहीं सकता । अगर कोई मारता है तो फौरैस्ट डिपार्टमैंट उसके खिलाफ केस बनाता है । उनकी वजह से रबी की फसल और खरीफ की फसल भी केवल चार आने किसान के हिस्से पड़ती है । वे इतनी हाय करते हैं जितनी बीमार आदमी भो नहीं करता । तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां कांटेदार तार लगाई जाए ताकि किसानों कौ कुछ राहत मिल सके । उनकी अधिकतर जमीन तो फौरैस्ट डिपार्टमैंट ने ले ली है । अगर किसी के पास दो एकड़ या चार एकड़ बची है और उसकी फसल को नील गाय खा जाए तौ आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किसान का क्या हाल होगा । इस ओर सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, जब सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेटस पर डिसकशन होगी तब ये इस तरह की सारी बातें कह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कहने दीजिए क्योंकि कई महीने के बाद सैशन आता है ।

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, मेरे हल्के की भी एक समस्या है जिसे मैं यहां हर बार कहता हूं । जमुनानगर का इंडस्ट्रियल पौल्यूशन वैस्टर्न जमुना कैनाल में आता है । वहां 15–20 गांव ऐसे हैं जिनके मवेशी उस पानी को पीकर मर जाते हैं । उसका समाधान करना बहुत जरूरी है । इसके इसके अलावा जब हवा चलती है तो वह भी पौल्यूशन की वजह से बदबूदार होती है । इनकी वजह से आस पास के गांवों में बीमारी फैल जाती है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात आ गई है ।

चौधरी हुक्म सिंह : स्पीकर सर, मैं भी आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में एक बात लाना चाहता हू । एकं क्वैश्चन के जवाब में आदर के योग्य मन्द्री महोदय ने लिखित रूप में बताया है कि बहुत सारे आदमी बाहर के यहां लगाए हुए है । स्पीकर सर, हम देहात में रहते हैं । हम देखते हैं कि हर गांव में आज यह हालत है कि कम से कम 50 प्रतिशत नौजवान मैट्रिक

पास बेकार घूमते है और 25–30 प्रतिशत से ज्यादा ग्रेजुएट नौजवान बेकार घूमते हैं । उनको कोई काम नहीं मिलता । यह बात रिकार्ड पर है औंर कई प्रश्नों के जवाब में यहां बताई भी गई है कि यहां बहुत से लोग यू ० पी० और विहार के लगे हुए हैं । जब हमारे घर में नौजवान बेकार और बेरोजगार बैठे है और उनको कोई काम न मिलता हो दी दूसरी कों दे दिया जाए तों उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है और असन्तोष फैलता है कि हमारा हक हमें नहीं मिलता । आज यही हालत ऐनीमल हसबैडरी डिपार्टमैंट में है, यही कोआपेटिव डिपार्टमेंट में है औंर यही एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में है । इसलये मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश कें नौजवानो को आगे आने का मौका दिया जाए, उन्हे ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । कहा दूसरा काम नौकरी का है क्योंकि उद्योग की कोई खास व्यवस्था यहां बनती नहीं औंर न ही दुकानदारी की व्यवस्था है । इसके अलावा स्पीकर साहब, जैसे सरदार लछमन सिंह जी कह रहे थे और अभी चौधरी दिलु राम जो बोल रहे थे, मेरे हल्के में भी नील गाय की वड़ी प्रौब्लम है । इसकी तरफ सरकार जरूर ध्यान दे । कृषि मन्त्री प्रसन्नी देवी जी जब कोसली में मण्डी का फाउन्डेशन स्टोन रखने गई थीं तो इन्होंने वहां किसानों की मांग पर यत्र कहा था कि नाहड बीड़ मे वाईल्ड लाइफ सैकचुअरी बनाएंगे । उम्मीद है कृषि मन्त्री महोदया जी ने इस सम्बन्ध मे जरूर कोई न कोई कार्यवाही की होगी । मैं उनका अग्रिम आभार प्रकट करते हुए निवेदन करता हूं कि नाहड

बीड़ के चारों तरफ यदि कांटेदार तार लगवा दी जाए तो किसानों को वहुत सुविधा मिल सकती है । किसानों का जो नुकसान होता है उमसे बचाया जा सकता है ।

कृषि मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : स्पीकर साहब, जहां तक नील गाय की बात है, इसके मारने की भारत सरकार की ओर से पाबन्दी है क्योंकि इसमें धर्म की बात आ जाती कुए । उनसे बात करके इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे । जहां तक सूअरो के शिकार की बात है, इस पर से पाबन्दी हटा दी गई है । अम्बाला जिले में इस बारे में काफी दिक्कत है । स्पीकर साहब जहां तक तार लगाने की बात का सम्बन्ध है, जगह जंगलात वालों की है । वह जब हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगी तो तार लगाने वाली बात भी हो जाएगी । इस बारे में कार्यवाही चल रही है ।

(4) मेवात क्षेत्र थे तालाबों में पानी की कमी होने तथा सिंचाई के लिए कोटला ओल का उपयोग करने सम्बन्धी

चौधरी अजमत खां : स्पीकर नाहर, सोहना से लेकर फिरोजपुर झिरका तक बहुत बुरी हालत है । अलवर रोड के दोनो तरफ जोहड़ो में पानी बिल्कुल नहीं है । लोग मवेशियों को वहां से कहीं और लेकर जा रहे हैं । उस इलाके में 5 नहरों का पानी पहुंच सकता बै । रनों वहां पर माइनर्ज हैं, जिनके जरिए उस इलाके में पानी पहुंच सकता है वे हैं, नूह इन्द्री, उजीना, बनारसी, जगवानी औंर उटावड माइनर्ज । लेकिन इन में से किसी भी

माईनर में पानी नही छोड़ा गया । पानी न छोडने की वजह से वे लोग अपना जोहड़ तक नहीं भर पाये हैं, खेत भरना तो अलग बात है । उस इलाके में जहां लोगों ने जानवरों को पानी की वजह से निकास दिया है, उसके लिये मेरा सूझाव है कि उस इलाके में जितनी भी नहरें बनी हैं अगर उनको जाकर देखें तो उटावड से आगे पानी नहीं गया । बनारसी और जंगवानी माईनर में भी पानी नहीं गया । ये नहरें 1977 से पहले की बनी हुई हैं । आज तक न तो वहां पर पानी पहुंचा है और न ही कोई रैवेन्यू सरकार को आता है । इन माईनर्ज पर हर साल मुरम्मत पर सरकार का लाखों रुपया खर्च हो गया है । मैंने सिंचाई विभाग को नंगवानी माईनर के बारे में लिखा था लेकिन उन्होंने मुझे आज तक कोई जवाब नहीं दिया कि मेरे द्वारा लिखे हुए पत्र पर क्या कार्यवाही की है । जिस वक्त चौधरी बंसी लाल जी पहने चीफ मिनिस्टर थे तो मेवात एरिया को बचाया जा सकता था । अगर उस स्कीम के ऊपर उस समय काम शुरू कर दिया गया होता जो उस समय तैयार की गई थी । कोटला में एक पम्प हाउस बनाया गया था जहां आउटलैट और इनलैट दोनों थे । मैं यह समझता हूं कि इनके अन्दर पानी को जमा करके आउटलैट से मलाई फीडर के जरिए उस इलाके को पानी दिया जा सकता शै । मलाई फीडर भी मुकम्मल है । कोटला लेक और तमाम दूसरी जितनी ड्रेनज हैं, वे पूरी मुकम्मल हैं । हैड भी सभी मुकम्मल हैं । अगर कहीं पर थोड़ा बहुत हैड बाकी है तो उस पर काम चल रहा है । अगर बरसात के दिनों में बारिश न हो तो गुड़गांव कैनाल से

पानी लाकर कोटला लेक में डाला जा सकता है । कोटला लेक मैं पानी डालने के बाद मेवात के बहुत बड़े एरिया को पानी दिया जा सकता है । इस स्कीम पर सरकार के कम से कम 16– 17 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं । मैं मती जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस स्कीम को फौरी तौर पर अपने हाथ में लें और मेवात को जो पानी मिलना चाहिए, वह दिलाया जाये । एस ० वाई ० एल ० का पानी तो उस एरिया में पता नहीं कब पहुंचेगा । यू ० पी ० वाले भी पानी नहीं देते । मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि कोटला लेक में पानी डाल कर वहां के लोगों को पानी दिया जाये । दूसरे, बरसात के दिनों में उस लेक में पानी स्टोर कर लिया जाये । अगर बरसात के दिनों में बारिश न हो तो जमना का जो पानी बेकार होता णै, उस पानी को उस लेक में वहुत आसानी से डाला जा सकता है । पानी लाने का कोटला लेक का सारा सिस्टम ठीक बना हुआ है । क्या सरकार सारे साधनों से पानी ला कर किसानों की मदद करने का विचार रखती है ?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, यह तो मुझे मालूम नही कि जो तालाब है उनमें पानी नहीं पहुंचा । दूसरे इन्होंने कोटला लेक की बात कही है कि उस लेक का इस्तेमाल सिंचाई के लिए और दूसरे कामो के लिए किया जाये । जहां तक कोटला लेक का सवाल है, मैंने भी खुद वहां पर 3– 4 बार जा कर मौका देखा है । यदि उस लेक की आसपास की कुछ जमीन को एक्वायर कर लिया जाये और उसको और गहरा कर दिया

जाये तो वहां पर बरसात का पानी और छोटी– छोटी पहाड़ियों का जो पानी आता है, उसको स्टोर कर लिया जाये से । इरिगेशन के लिए वह पानी इस्तेमाल हो सकता है और रिचार्जिग के लिए भी काम आ सकता है । इस बारे में, मैं इन्हें यह बताना चाहूंगा कि उस इलाके के जो किसान हैं, जिनकी वहां पर जमीन है कि वे इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि वहां की जमीन एक्वायर की जाये । उनकी यह तो मांग रहती है कि उनकी जमीन में बरसात के दिनो में जो पानी जमा हो जाता है, वह अगली फसल बोने से पहले पहले निकाल दिया जाये ताकि वे अगली फसल बो सकें लेकिन वे इस बात के लिए राजी नहीं हैं कि उनकी जमीन को एक्वायर किया जाये । सरकार ने वहां पर कुछेक पम्प हाउस भी बना रखे हैं लेकिन वे जमीन एक्वायर करने के लिए नहीं देते । वे अपनी जमीन खुद अपने पास रखना चाहते हैं । ये वहां से एम ० एल ० ए ० हैं और दूसरे जो इनके राजनैतिक साथी हैं, वे और ये दोनों लोगों को जमीन एक्वायर करने देने के लिए परसुएड करें और सरकार की इस बारे में मदद करें । वे अपनी मदद सरक को दें ताकि इस स्कीम को चालू किया जा सके । एक बात इन्होंने यह कही कि व हां पर जो पौन्डज हैं, उनमें पानी नहीं है । जहां तक नहरों में पुरा पानी नहीं जाता, उ सका जवाव तो इन्होंने खुद ही दे दिया कि एस ० वाई ० एल ० का पानी ही गुडगांव के एरिया मैं जाना है । जब वह पानी मिलेगा तभी पूरा पानी उस एरिया को मिल पायेगा । इस वक्त सरकार ने, खास तौर से डी ० सीज ० को हिदायतें दी हुए हैं कि जोहड़ों में

पानी अवश्य पहुंचाया जाये । इसके लिए डी ० सीज ० को कुछ फण्डज भी दिए हुए हैं ताकि गांवों के पौण्डज में पानी डलवाया जा सके । ऐसी ही हिदायतें नहर के अधिकारियों को भी दी हुई हैं । अगर मेरे दे यह बताएंगे कि कौन से एरिया के गांवो के पौण्डज के पानी नही पहुंचा है तो हम दुबारा कोशिश करेंगे कि उन पौण्डज में पानी डलवाया जा सके ।

(5) अटेली मंडी में सब – टेरजरी खोल ने संबधी

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, अटेली मंडी में एक सब–ट्रेजरी खोलने की बात कई दफा सरकार के नोटिस में लाई गई लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ । वहां सै महीने में लगभग एक करोड़ रुपया ट्रेजरी में जमा होता है । वहां बहुत से हाई स्कूल्ज हैं, फौजी अक्सर भी बहुत हैं । उन सबको पैन्शन लैने नारनौल जाना पड़ता है जहा काफी लम्बी लाईन लगी होती है । इसमें सरकार का ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा । स्पीकर साहब वहां से होने वाली कलैक्शन इस बात को. जस्टिफाई करती है कि अटेली मंडी में एक सब–ट्रेजरी खोली जाए । तो मैं फाईनैसं मिनिस्टर साह व से प्रार्थना करूंगा कि वे इस तरफ अवश्य ध्यान दें । यह केस पहले राईप हो गया था लेकिन पता नहीं बाद में किस तरह ड्रौप हो गया ।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर) : ठीक है जी, इसको देख लेंगे।

वर्ष 1986– 87 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स (पहली किश्त) पर चर्चा तथा मतदान

(1) राज्य के राजस्वो पर प्रभारित अनुदानों पर चर्चा ।

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्ष 1986–87 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स (पहली किश्त) पर डिसकशन होगी । जो आनरेबल मैम्बर्ज चार्जड आईटम्ज को डिसकस करना चाहें, वे कर सकते हैं तथा पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाईम सेवा करने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज एक साथ पढ़ी गई तथा मूव –ही गई समझो जाएगी । आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर बोल सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें । डिसकशन के बाद डिमांड्ज हाऊस की वोट के लिए पुट की जाएगी ।

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,05,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1987 in respect of Demand No. Revenue.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 11,25,000 for capital expediture be granted to the Governor to defray charges that will come' in the course of payment for the

year ending 31st March 1987 in respecs of Demand No. 17—Agriculture.

श्री भले राम (बडौदा–अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, मैं इन सभी डिमांडज पर थोडा थोड़ा बोलना चाहूंगा । हरियाणा सरकार मे कुछ खर्चा किया है जो बहुत जरूरी था और अब यह उसकी मंजूरी हाउस से लेना चाहती है । डिमांड नं० 4 रैवेन्यू की है । सन् 1985 में हरियाणा के कई जिलों जैसे जींद, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में भयंकर बाढ़ आई और सरकार ने फौरी तौर पर लोगों को राहत देने के लिए, वहां से पानी निकालने के लिए, पशुओं को बीमारी से बचाने के टीके लगाने के लिए और लोगों को –दूसरी कई प्रकार की सहायता देने के लिए साढ़े चार करोड़ रुपया खर्च किया । स्पीकर साहब, फ्लडज हर साल आते हैं और बात भी कुछ उलटी होने लगी है । पहले फ्लडज सोनीपत और रोहतक के इलाकों में आया करते थे लेकिन अब फ्लडज वहां आते हैं जहां पानी 100 फुट से भी नीचे हुआ करता था । हमने कभी स्वपन में भी नहीं सोचा था कि कभी सिरसा और हिसार के इलाकों में भी फ्लडज आएंगे । फलड से लोगों की बरबादी हुई । मती महोदय को पता है कि हर साल फ्लड आते हैं और हर साल करोडों रुपया इस मद पर खर्च किया जाता है चाहे वह दवाईयां खरीदने, पानी निकालने या चारे के लिए खर्च किया जाता हो । क्यों नहीं सरकार एक कर ही इन ड्रेनों को, चाहे वह पुरानी है या नई बनानी है, बना दे ताकि आइन्दा लोगों को परेशानी न हो । जव

हम अपने एस० ई० और एक्सीयन से यह मांग करते हैं कि फलो ड्रेन को बनाया जाये तो वे कहते हैं कि पैसा नहीं है । सभी को पता है कि दो साल से बारिश नहीं हुई जिसके कारण फ्लड नहीं आये लेकिन जिन ड्रेनज को बनाने की प्रोपोजल है, उन पर अब हाल में कोई विचार नहीं किया जाता । पिछले दो तीन साल से तो बारिश नहीं हुई लेकिन मेरा विश्वास है कि इस साल बारिश होगी । इसलिए जो स्कीमें अधूरी पड़ी हैं उन्हें जरूर बनवाया जाये । आप सभी मैम्बरान को पता है कि हमारे गोहाना में पिछले सालो में बहुत जबरदस्त फलड आया था, शायद हरियाणा में इतना जबरदस्त फलड कभी नहीं आया । अब भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, बेशक आप वहां के अफसर साहेबान से पता कर लें । वजीरपुर–खन्दराई ड्रेन है, उस पर कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होने वाला है । केवल तीन या साढ़े तीन लाल रुपया खर्च होगा, केवल लोगों को कम्पनसेशन देना है । इस ड्रेन को बनाना बहुत जरूरी है । उन गांवों के एरिया में अब भी पानी खड़ा हुआ है । इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि उन ड्रेनज को बनाने में प्राथ– मिकता दी जाये ताकि लोगों को सहूलियत हो सके । अगली बरसात के आने से पहले इस ड्रेन का बनना जरूरी है । इसी तरह से दूसरी पेलपा ड्रेन है, वह भी बनानी जरूरी है । इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूगा कि ठेकेदार और दूसरे लोगों से बुगरा लिंक वेसा है । ठेकेदार हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने फलां जगह पर काम तो कर दिया लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला । जब तक उन्हें पिछला पैसा नही मिलता है,

वे काम करने से इन्कार कर देते हैं । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो उनका एरियर पड़ा है वह देने का कष्ट करें ताकि आगे काम चल सके ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, घग्गर नदी में बाढ़ आ जाने के कारण सिरसा तहसील के अलानूर और भामबूर गांव नष्ट हो गये थे । इन गांवों के लोगों को बसाने के लिए सरकार ने जमीन एक्वायर की है । जिन लोगों की जमीन ली गई थी उन्हें कम्पनसेशन कम मिलने के कारण वे कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया, इसलिए 23,54,160 रुपया सरकार को देना पड़ा । यह देना चाहिए भी था क्योंकि पहले कम कीमत लगायी गई थी । इसके अलावा, हैल्थ डिपार्टमैंट के डा० नसीब सिंह धूल, जिस की सरकार ने सर्विस टरमिनेट कर दी थी, वह सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में चला गया और उसे सरकार ने वापिस सर्विस में भी लिया और 70 हजार रुपये भी देने पड़े । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसी भी सरकारी आदमी की सर्विस टरमिनेट करने से पहले रूल्ज रैगूलेशन्ज को देखे लेना चाहिए । उस असे के दौरान उसने काम भी नहीं किया और सारे बैनीफिटस भी ले गया । इसलिए किसी की नौकरी खत्म करने से पहले सारी बातों को देख लेना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, श्री हजारा सिंह ड्राईवर, स्वास्थ्य विभाग का था। उस ड्राईवर से श्री खिलाराम नाम का व्यक्ति मर गया । उसकी औरत श्रीमती रूक्मणी देवी ने मुआवजे का केस दायर कर दिया । उसके दावे के कारण कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया और सरकार को 15 हजार रुपये उसे कम्पनसेशन देना पड़ा । सरकार को देखना चाहिए था कि जो ड्राईवर जीप चला रहा था आया वह अन ट्रेन्ड तो नही था ? अगर अन–ट्रेन्ड था तो उसके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए । इसके अलावा, श्री नौराता राम की श्रीमती शान्ति देवी को 16,000 रुपये मुआवजे की रकम देनी पड़ी है । श्री नौराता राम अम्बाला शहर में वार्ड कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा था । वह आपरेशन थियेटर में उच्च दाब भाष्प जीवाणु नाशक यत्न चला रहा था । ड्रम, जिसमें ग्लूकोज की बोतलें पड़ी थीं फट गया, जिसके कारण उसकी छाती में टूटी बोतलों का कांच तथा उबलता हुआ पानी लगा और उसकी मृत्यु हो गई । उनकी औरत ने कोर्ट में केस कर दिया और उसे 16 हजार रुपये कम्पनसेशन के रूप में दिया गया । अब देखना यह चाहिए कि जो वह काम कर रहा था, उसकी वह ड्यूटी थी या नहीं? उसमें डाक्टर की लापरवाही तो नहीं थी? कहीं यह तो नहीं कि उस काम को करने की ड्यूटी डाक्टर की हो और जिम्मेवार दूसरे को ठहरा दिया गया हो । इस बारे में सरकार को इन्कवायरी करनी? चाहिए कि उसकी मौत का क्या कारण था । इन्कवायरी करके जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अगली डिमान्ड सोशल वैल्फेयर के बारे में है । पहले यह सैन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम थी । अगर कोई हरिजन पांच एकड़ जमीन खरीदना चाहे तो उसे दो हजार रुपये सबसिडी सरकार की तरफ से दी जातो थी लेकिन उस पांच एकड़ जमीन की कीमत 4,500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । वर्ष 1964 मैं 31 हरिजन फैमिलिज को दो हजार रुपये के हिसाब से 62 हजार रुपये व्याने के रूप में दिये और बाकी रुपया बैकों से कर्जा ले कर देना था लेकिन बैकों ने इस बिना पर पैसा नहीं दिया कि कुछ जमीन शामलात की है इसलिए वह रजि– स्टरी नहीं करा सकते । रजिस्टरी न कराने के कारग वह ब्याना भी गया । इस बारे में सरकार कोर्ट में भी लडी लेकिन फिर भी 8 हजार रुपया सरकार पर डाल दिया जो सरकार को देना पड़ा । अगर कोई हरिजन जमीन लेना चाहता है तो परकार उसे दो हजार रुपया सबसिडी देती थी और बाकी अपना लगाते थे लेकिन अब यह स्कीम सरकार ने बन्द कर दी है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यह स्कीम बन्द नहीं होनी चाहिए । दो हजार रुपये सरकार की ओर से सबसिडी मिलती रहे और बाकी पैसा वह अपनी तरफ से लगा लेगा । अगर एकाध किला हरिजन भी खरीद ले तो उसे यह गिला नहीं रहेगा कि मेरे पास जमीन नहीं है । हरिजन कोरा यह कहते रहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है । ऐसा करने से उनकी मदद भी हो जायेगी और जो सामाजिक प्रोब्लम है वह भी हल हो जायेगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट सोशल वैल्फेयर आफिसर की जीप से श्री अवतार सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गया और बाद में वह मर गया लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि उस जीप को कौन चला रहा था, किस से वह एक्सीडैन्ट हुआ है । ड्राईवर का नाम नहीं दिया । हो सकता है कि स्पेशल वैल्फेयर आफिसर खुद जोर को चला रहा हो । हमें पता करना चाहिए कि उस टाईम कौन जीप चला रहा था और कैसे वह मौत हुई ' इसके अतिरिक्त डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैक ई । ये बैंक भिवानी, गुडगांव, सोनीपत और जीन्द में भी हैं । इन बैंकों को सेवर कैप्टिव हरियाणा सरकार भी देती है । पंजाब नेशनल बैक और सिंडीकेट बैंक इन ग्रमीण बैंको के प्रयोजक बैक है। ये प्रयोजक बैक 35 परसेन्ट, भारत सरकार 50 पर सैन्ट और राज्य सरकार 15 परसैन्ट शेयर देती है । अब इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं इसलिए गवर्नमैंट आफ इंडिया ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि 15 परसैट शेयर कैपिटल और दे ताकि उनका कैपिटल बढ़ सके । भारत सरकार ने उनसे साढ़े ग्यारह लाख रुपया मांगा है जौ कि सरकार को देना जरूरी है । लेकिन इमके साथ साथ मैं एक बात अर्थ करना चाहूंगा कि ये रूरल बैकस लोगों के साथ कोआपरेट नही करते है, उन्हें परेशान करते हैं और उनका प्रोसीजर बड़ा कम्पलीकेटिड है । इन बैंकों का रेट आफ इन्ट्रैस्ट भी ज्यादा है । किसानों और गरीब आदमियों के लिए इन बैंकों को अपना प्रोसीजर सरल करना चाहिए ताकि गरीब आदमी भी

उनसे फायदा उठा चूके । इन शबदों के साथ मैं चाहूंगा कि हाउस इन डिमान्डज को पास करे ।

श्री लछमन सिंह (कालका) : डप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमान्ड नं ० 4 पर बोलना चाहूंगा । वैने तो इसमें कोई खास बात नही है । सरकार ने फ्लड के लिए पैसा मांगा है लेकिन जो हैरतअंगेज बात है वह यह है कि जो लैन्ड–इक्वीजीशन की गई उसके लिए सरकार ने 78, 823 रुपये कम्पनसेशन के रूप में जमीदारो को दिये लेकिन जब जमीदार कोर्ट में चलें गये तो उन्हे वहां से 23,54,160 रुपये मले । अब आप इस बात का अन्दाजा लगाइये कि पहले उन्हें कितनी कीमत दी यई और बाद में कोर्ट ने कितनी की मत दी । आज भी यही हालत है । किसानों को जो मुआवजा दिया जाता है वह बहुत कम दिया जाता है लैन्ड इस्वीजीशन अफसर का काम करने का तरीका आज भी दकियानूसी है, वही पुराने ख्याल का है, उसी तरीके से उन जमींदारी को पैसा दिया जाता है । सरकार ने कानून बना दया है कि जमीदारों को मुआवजा मौजूदा रेटस पर दिया जाये लेकिन किसाने को परेशान करने के लिए लैन्ड इक्वीजीशन अफसर, पिछले पांच साल की पुरानी रजिस्टरी मांगता है ताकि वे उसे भी पैसा दे । आप इसी बात से अन्दाजा लगा लें कि सरकार की तरफ से 78 हजा र रुपये का मुआवडा दिया गया जब कि कोर्ट ने 23 लाख के करीब कर दिया । किसान की जमीन की कीमत अगर पहले ही सरकार कम कर दे तो उसे बहुत मुश्किल हो जाती है । अगर वह कोर्ट में

जाता है तो वहां से उसे पैसा मिल भी सकता है न भी मिले । लेकिन अब जो यह फैसला आया शै उस से टैनडेन्सी का पता लगता है । अब सूप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि तीस परसैन्ट सरकार इन्ट्रैस्ट भी दे । लैन्ड इक्वीजीशन आफिसर्ज के खिलाफ सरकार को ऐक्शन लेना चाहिए । जब जमींदार की जमीन की कीमत लगाते हैं तो वे उनसे पैसा लेते हैं । वे पांच–छः तरह की कैटेगरी बना लेते हैं कि तुम्हारा इतना पैसा काटा जाये गा । वह अनपढ़ किसान बडी मुश्किल में पड़ जाता है । वह आफिसर नही समझता कि जिस किसान की जमीन एक्वायर हो गई उसके पास क्या बचा है । वह अपना घर गवां बैठा है । वह अपने बाप दादा की जमीन पर खेती करता था वह भी गंवा बैठा तो उसके पास क्या बचा है । उपाध्यक्ष महोदय, किसान को कितना ही पैसा मिल जाये, वह उसके पास नहीं रह सकता । आपाको पता है कभी कोई लड़का उसका नालायक निकल जाता है तो कभी वर के अखराजात बढ़ जाते हैं जहां पर पैसा खर्च करना पडता है । जमीन ही एक ऐसी चीज है, जिस पर वह अपना कुछ हद तक गुजारा करता है । को सख्त हिदायत जारी करनी चाहिये कि किस को उसकी जमीन का मार्किट रेट मिलना चाहिये । अगर उसको–कम पैसा मिलता है तो वह कोर्ट में जायेगा । उस बेचारे का पैसा खर्च होगा । आजकल गिनती के कुछ वकील हैं जो मुनासिब फीस लेते हों वरना जब वह देखते हैं कि इसको लाखों रुपये मिलेंगे तो 15– 20 हजार रुपया फीस मांगते हैं । मुझे पता है रैवेन्यू मिनिस्टर साहब बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हुँ । वह बैठे–बैठे

मेरी इस बात को तसदीक भी कर रहे हैं । मेरी रिक्वैस्ट है कि वे इस बात के लिये भी अपने महकमे को खैचें । मुझे पता है कि उन्होंने अपने महकमे को खीं चा भी है । अब वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ नही है । काफी हद तक उन्होंने गड़बड़ टूर कर दी है । शायद एक्वीजी शन आफ लैंड की प्रोसिडिंग्ज का काम महकमा माल से ताल्लुक रखता है । इन डिमांड्ज में डिस्कशन की तो को ई बात नहीं है । स्टेट गवर्नमैंट का तो यह पैसा भी नहीं है । मैं अन्त में इन शब्दों के साथ दरख्वास्त करूंगा इसको पास कर देना चाहिये । धन्यवाद ।

11.00 बजे

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर) : डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ मांगें जो सदन में आयी हैं, मैं भी उनके बारे में कुछ कहना चाहुंगा । अभी माननीय सदस्य सरदार लछमन सिंह जी लैन्ड एक्वीजीशन की पेमेंट के बारे में बोल रहे थे । वास्तव में कई जगहों पर इस बात की दिक्कत आती है कि लोगों को मार्किट प्राईस नही मिल पाती । अभी हाम ही में हुड्डा ने मेरे इलाके में दो–तीन गांवों रतगल, देवीदास पुरा, पिपली और उमरी में जमीन एक्वायर की– है । उनको मार्किट प्राईस नही दी गयी । लोगों की मेरे पास शिकायत आयी है । मैने गवर्नमैंट को लिखा कि इस प्रकार से लोगों कई शिकायत है लेकिन मुझे जवाव उसी प्रकार का दे दिया जो बहुत ही गलत बात है। कुरुक्षेत्र के आस–पास के इलाके में जमीन की कीमत एक लाख रुपया प्रति

एकड़ से भी ज्यादा है । जब इतना कम मुआवजा दें गे तो लोगों को कोर्ट में जान ही पडेगा। दो–तीन साल लगेंगे क्योंकि इतना लम्बा–चौडा प्रोसैस तो यह है ही । सरकार ने बार–बार कहा है लोगों को मार्किट प्राईस दी जा रही है लेकिन असली मायनों में यह हिदायतें इम्पलीमैंट नही हो रही हैं । सरकार की तरफ मे तो पूरी तरह से हिदायतें हैं लेकिन कई अधिकारी ऐ ते णै, जो उनको इम्पलीमैंट नही करते । मैं रै वेन्यू मिनिस्टर महोदय से जो यहां पर बैठे हुए हैं और हुड्डा के अधिकारियों से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे किसानों को उनका उचित मुआवजा दिलवाये । 5 साले की एवरेज का चक्कर अब वे छोड़ दें । इसमें एक दूसरा कारण यह भी है कि जब किसी एरिया को 5 साल पहले कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसमें कोई सेल–परचेज नहीं होती । फिर पता कैसे चल सकता है कि वहां पर क्या भाव है । इसलिये आस–पास के एरिया की प्राइस देख नई चाहिये और उसके हिसाब से मुआवजा देना चाहिये । एक बात के बारे में कई सदस्यों ने मांग रखी कि नील गाय का कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जाये । मेरा भी कहना व ह्र है कि मेरे हल्कें में एक बीड़ सौटी के नाम से एक जंगल है बसमें बहुत नील गाय हैं । इसके बारे में लोगों की मांग है कि फौरैस्ट की चारो ओर से फैन्सिंग कर दी जाये ताकि लोगों के खेतों में जो नुक्सान होता है, वह कम हो सके । इससे काफी हद तक लोगों का नुक्सान बच सकता है । इस बारे में मेरी रैवेन्यू मिनिस्टर साहब से बात भी हुई थी । वह

भी मेरी फौन्सिग की बात से फी करते हैं । इससे काफी हद तक प्रौब्लम हल हो जायेगी ।

इसी प्रकार से डिप्टी स्पीकर साहब, मांग नं ० 17, एग्रीकल्चर से' ताल्लुक रखती है, उसके बारे में आप 'जानते हैं कि कुरुक्षेत्र जिला पैदावार के मामले में मारे देश में नम्बर एक पर है । फिर भी' कई कमियां रह जाती हैं जिनको सरकार दूर करने की कोशिश करती है । इनमें एक कमी यह है कि इस क्षेत्र को बिजली पूरी नही मिल पाती । जैसे आज सुबह ही आई ० पी ० एम ० साहब ने बताया कि उस इलाके में दो नहरों का प्रोवीजन करने जा रहे हैं–एक लाडवा कैनाल और दूसरी नलवी कैनाल, मैं सरकार मे अनुरोध करूंगा कि अगर इन दोनों नहरों का काम जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाये तो इससे लोगों को सुविधा मिलेगी । एक तो इससे ग्राउन्ड वाटर टेबल जो काफी नीचे चला गया है, वह ठीक हो जायेगा, दसरे वर्षा के दिनों में लोगों को पानी मित्र सकेगा और हमीर यहां प्रोडक्शन पहले के मुकाबले में दुगुनी हो सकेगी । हमारे यहां, 'आपको पता ही है जीरी, गेंहु और गन्ना काफी पैदा होता है ।

मांग संख्या 10 हैल्थ के बारे मैं है । इस बारे में सरकार पूरा–पूरा प्रयत्न कर रही है कि गांव–गांव में प्राइमरी सब–सैटर खोले जायें और लोगों को हैल्थ के मामले में सुविधा दी जाये । मेरे हल्के में प्राइमरी हैल्थ सैटर और आयुर्वेदिक डिस्पैसंरियां बहुत ही कम हैं । लाडवा मे तो एक छोटा सा

अस्पताल है लेकिन वह उस एरिया की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर सकता । वहां पर पंचायत डेरा ने 6 एकड जमीन हैल्थ डिपार्टमैंट को देने का वायदा किया है ताकि वहां पर कम्युनिटी हैल्थ सैटर खोला जा सके । उसके लिये एक प्रोपोजल सरकार के पास आलरेडी आ चुकी है । मैं कई बार सरकार को लैटर भी लिख चुका हूं कि वहां पर एक कम्युनिटी हैल्थ सैटर खोल दिया जाये । मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी कम्युनिटी हैल्थ सैंटर खोल दिया जाये क्योंकि रादौर और कुरुक्षेत्र के बीच के प्रिया में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो उस एरिया को फीड कर सके । इससे वहां के लोगों को काफी सुविधा मिल सकेगी । इसके लिये पंचायत ने भी जमीन देने के लिये प्रस्ताव किया हुआ है । इसी प्रकार जैसे कि सरकार ने बताया है, कुछ आयुर्वेदिक डिस्पैसंरियां खोलना सरकार के विचाराधीन है । इसके लिये मैं यह रिक्वैस्ट करूंगा कि मेरे यहां पर तीन जगहों पर, बनी, दबखेडा और कसेरला में आयुर्वेदिक डिस्पैसरियां खोल दी जायें । यहां पर बिल्डिगें भी बनी हुई है और केस भी मुकम्मल होकर आ चुका है । मेरे ख्याल में कम से कम इन तीनों जगहों पर यह डिस्पैसंरियां अवश्य ही खोल दी जानी चाहियें ।

इसके अलावा डिमांड नं ० 13 सोशल वैल्फेयर और रिहैबलींटेशन के बारे में है । इस बारे में तो यह सरकार काफी जोर–शोर से काम कर रही है । जिन लोगों को सहायता की

जरूरत है उन सभी लोगों को पूरी सहायता मिल रही है । जो अपंग और बूढे है उनको पैशन मिलती है। इसी प्रकार विंडोज को भी पैशन मिलती है । सभी के केस प्रोसैस हों रहे हैं । कुछ ऐप्लीकेशन्ज काफी देर से पैडिंग पडी हैं । मैं सरकार सरकार से गुजारिश करूंगा कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाये ताकि उन लोगों को भी पैशन मिल सकै । मैं ओर ज्यादा न कहता हुआ इन मांगों का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

चौधरी लीला कृष्ण (फतेहाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब हाउस में जो सप्ली मैंटरी डिमांड्ज रखी गई हैं मैं उन पर बोलने के लिए मैं खडा हुआ हूं । सबसे पहले मैं डिमान्ड नम्बर 13 पर बोलना चाहूंगा । यह डिमान्ड सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट की है और इसमें 15 लाख 33 हजार रुपया मांगा गया है । यह मामूली रकम है और इसका पास कर देना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, इस डिपार्टमैंट का जो वे–आफ–वर्किंग है वह बहुत ज्यादा डिफैक्टिव है । इस बारे में मैंने पिछले सैशन में भी कर्ज की थी और अब फिर कहना चाहता हूं । अपाहिज, विडो और बूढ़े लोग मुश्किल से फार्म लेते हैं और फिर उसको तसदीक कराते हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, विडो को भी कहा जाता है कि डाक्टरी सर्टिफिकेट लेकर आओ फिर उसको तहसीलदार अटैस्ट करता है । उसके बाद वह फार्म सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट के आफिस में पहुंचता है लेकिन उसके पश्चात उस आफिस में एतराज लगा दिया जाता है । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पास सबूत है कि सारे कागज

सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट में पहुंचते–पहुंचते फट गए और लोगों को दुबारा कहा गया कि आप फार्म दुबारा भरी । बूढ़े. बेचारे फार्म भरते–भरते ही मर जाते हैं लेकिन उनको पैन्शन नहीं मिलती । मेरा कहना यह है कि इस प्रोसीजर को इतना सिम्पल बनाया जाए कि लोगों को आसानी से पैसा मिल सके । आप अन्दाजा लगा सकते है कि एक अन्धी औरत कहा से फार्म लाए और कैसे वह दफ्तरों के चक्कर काटती फिरे डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पास बीसों सबूत हैं जिनमे लोग मर गए लेकिन उनको कुछ मदद नहीं मिली । मैं तो चाहता था कि बिडोज, बूढ़ों और अपाहिजों को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए और ज्यादा पैसा उनके लिए रखा जाए और इन प्रोसैस को इतना सिम्पल बनाया जाए कि इन अपाहिज और अन्धे लोगों को आसानी से पैसा मिल सके ताकि ये लोग सरकार की स्कीम्ज का अधिक से अधिक फायदा उठा सकें । दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की ऐप्लीकेशंज पैडिंग हैं उनको जल्दी प्रोसैस करके जल्दी से जल्दी पैन्शन दी जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें मैडीकल की भी डिमांड है । यह बात ठीक है कि बहुत थोड़े से पैसे की डिमाण्ड है, यह पास होनी चाहिए । लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर फैमिली प्लानिंग के लिए लोगो. को दोबारा मजबूर किया जाता है । डाक्टर्ज कहते हैं कि हमारा इतना कोटा निर्धारित है, आप केस लाओ । डिप्टी स्पीकर साहब, कहीं ऐसा न हो कि यह वात आगे चलकर नुक्सानदायक

बन जाए । मेरा कहना है कि फैमिली प्लानिंग की जाए अच्छी बात है लेकिन परसुएशन से की जाए । इसके लिए एड– वरटाइजमैंट किया जाए । लेकिन लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर न किया जाए । मजबूर करने से ऐसा न हो कि नुक्सान उठाना पड़ जाए। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री जगदीश नेहरा (रोड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नम्बर 4, 10, 13 और 17 के बारे में अर्ज करना चाहूंगा । डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक मांग नम्बर 4 का सवाल है इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है और वह ठीक है । उपाध्यक्ष महोदय, जिस–जिस जिले में फलड आया और वहां पर मकान गिरने का तो मुआवजा दिया गया, वह बहुत कम है । आप खुद ही सोच सकते हैं कि आज चार सौ रुपए में कोई क्या कर सकता है । चार सौ रुपए में तो कुछ भी सामान नहीं आता । मेरी सरकार से अर्ज है कि मुआवजे की रकम को बढ़ाया जाए । जिन लोगों के मकान गिरते हैं उनका मुआवजा चार सौ रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपया कर देना चाहिए ताकि जिसका मकान गिर जाए वह उसको दुबारा बनाने की हिम्मत स्पर सके । सरकार ने बाद के समय कुछ सुविधाए भी दी जैसे मैडीसन की सुविधा, रोडज रिपेयर करने की सुविधा और वाटर वर्कस रिपेयर करने की सुविधा दी और यह कहा गया कि जहां पर पानी खइ एं उसको निकाला जाएगा । डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक डी–वाटरिंग का सम्बन्ध है, डी–वाटरिग केवल शहरी क्षेत्रो में ही किया गया है जब

कि गांवों में इस दिशा में काम नहीं किया गया । मेरे हल्के में कई जगहे ऐसी हैं जहां पानी खडा हुआ है लेकिन अभी तक डी–वाटरिंग नहीं की गई । जो फ्लड कन्ट्रोल कमेटी बनी थी उसने एलान किया था कि 15 दिसम्बर सके जहां –जहां पानी इक्ट्ठा है, उसकी डी –वाटरिंग कर दी जाएगी ' लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा नहीं किया गया । यह सरकार ने बहुत बड़ी गल्ली की है । मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार डी–वाटरिंग का काम शहरों में किया गया है उसी तरह से रूरल एरियाज में भी डी –वाटरिंग का काम किया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, कम्बैन्सेशन के मामले में भी सरकार काफी लिबरल है । इसलिए हरेक डिपार्टमैंट को काफर पैसा पहले ही कम्पैनसेशन के लिए रखना चाहिए । लोग हाई कोर्ट में जाते है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और हर बार कम्पैनसेशन का पैसा बढ़ता ही जाता है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अधिक में अधिक पैसा कम्पैनसेशन के लिए रखा जाए ताकि दुबारा पैसा न मांगना पड़े, जितना पैसा बजट में रखा जाए उसी से काम बन जाए । इन डिमाण्डज में पेमैन्ट आफ सैलरी के लिए पैसा मांगा गया है । किसी आदमी के हटा दया गया और कोर्ट ने उसको रीइनस्टेट कर दिया, उसके लिए यह पैसा मांगा गया है । मेरी सस्पैशन है कि सरकार को सोच समझ कर किसी को हटाना चाहिए और जो औफिसर्ज इस मामले में गल्ती करते हैं उनको भी पूछा जाना चाहिए । अगर किसी ऐम्पलाई के हाई कोर्ट ने

री–इन्स्टेट कर दिया है और केस कम जोर है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं हैं । इस केस में 76 हजार 5 सौ रुपया मांगा गया है । यह भी पास हो जाएगा लेकिन इस तरफ सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि वैसे ही किसी ऐम्पलाई को नहीं हटाया जाना चाहिए ।

इसी तप से ऐक्सीडेंट में जो लोग मारे जाते हैं उनको कम्पैनसेशन देने के लिए भी पैसा मांगा गया है । यह पैसा पन्द्रह या सोलह हजार है । मेरी इस वारे में पखं है कि जो गरीब मांग ऐक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उनको कम्पैन्सेशन देने के बारे में सरकार को लिवरल होना चाहिए । लैड इक्वीजीशन का कम्पन्सेशन देने के लिए 14 लाख 80 हजार 165 रुपया मांगा गया है । अमर यह पैसा पहले ही दे दिया जाता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न जाना पड़ता । डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 11 लाख 25 हजार रुपया शेयर कैपीटल के रुप में दिया गया है । बैक का शेयर कैपीटल तो पहले ही फिक्स था उसके लिए दुबारा पैसा क्यों मांगा गया है। जो कंट्रीब्यूशन करना था वर पहले ही बजट में किया जाना चाहिए था और औफिसर्ज को इसका पहले ही ज्ञान होना चाहिए था लेकिन फिर भी जो डिमाण्डज हैं, ये वाजिब डिमाण्डज हैं और ये पास की जानी चाहिएं ।

बहिन शान्ति देवी (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेट्स के सम्बन्ध में अपने विचार रखने के लिये

खड़ी हुई हूं । सब से पहले मैं डिमांड नम्बर के बारे में विचार रखूंगी । डिप्टी स्पीकर साहब, जिन जिन क्षेत्रो में प्रभु की कृपा से बाढ़ नहीं आई हूं, वहां के लिये भी पैसा निश्चित किया हुआ था । उस पैसे का सदुपयोग पानी की निकासी, गन्दे नाले व सिवरेज सिस्टम के सुधार के में सरकार को पूरा–पूरा ध्यान रख कर करना चाहिये । इस से ज्यादा आबादी वाले इलाकों को लाभ होगा ।

अप मैं डिमांड नम्बर 10 जोकि चिकित्सा से सम्बन्धित है, के बारे में कुछ कहना चाहूंगी । करनाल एक बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है और वहां का हस्पताल 100 साल पुराने एक भवन में है । वहां की आबादी अब बहुत अधिक वढ गयी है, आवागमन के साधन भी ज्यादा हैं और गांवों से शहर की ओर लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया है । वैसे भी करनाल जी० टी० रोड पर स्थित है रोज ना ऐक्सीडैंट्स भी बहुत होते हैं, रोगियों की दशा भी बहुत शोचनीय ई । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को हस्पताल के नये भवन का निर्माण करवाना चाहिये । नये भवन निर्माण के लिये काफी देर पहले से उसका शिलान्यास भी हो चुका है परन्तु न जाने किस कारणवश भवन निर्माण का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है । केवल मात्र डाक्टरों के रहने के लिये भवन अवश्य बना दिये गये हैं । इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अब जो पैसा रखा गया है, इसमें से कुछ न कुछ पैसे का प्रवन्ध इस काम के लिये अवश्य किया जाए ताकि आने वाले महीनों में इसका निर्माण कार्य आरम्भ हो सके

और लोगों को राहत मिल सके । लोगों को तसल्ली हो क्योंकि करनाल के लोगों की यह बड़ी देर से चली आ रही एक जायज डिमांड है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 13 जोकि पुनर्वास से सम्बन्ध रचती है पर अपने विचार रखूंगी । डिप्टी स्पीकर साहब, करनाल के अन्दर पाकिस्तान बनने के बाद वहां से आने वाले लोगों के लिये कई नई बस्तियां माडल टाउन जो प्रेम नगर, राम नगर, व कृष्णा नगर के नाम से बसाई गयी थीं और इन बस्तियों के लिये जितना पैसा मिला था उस में से 20–30 लाख रुपया अभी भी रिहैबलीटेशन डिपाटैमैंट के पास बचा पड़ा है लेकिन वह पैसा पता नहीं किस हैड में डाल दिया गया है । उस पैसे का सदुपयोग इन बस्तियों के सुधार हेतु होना चाहिये ताकि इन बस्तियों के लोगों को उचित सुविधाएं प्राप्त हो सके । मेरी सरकार' से सविनय प्रार्थना है कि इस पैसे की जल्दी ही खोजबीन करके यह राशि निकलवायी जाए और जिस काम के लिये यह पैसा रखा गया था, उसी के लिये इस्तेमाल किया जाए ताकि इन पैसे का सदुपयोग उन्हीं बस्तियों के निर्माण हेतु किया जा सके और लोगों को भी राहत मिले । उस वक्त काफी काम इन बस्तियों का अधूरा रह गया था । यहां सीवरेज व पानी बगैरह का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । उस वक्त यह सहूलियतें नहीं दी गई थीं । इससे करनाल की जनता को कुछ सुख मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी । करनाल शहर की खूबसूरती बढ़ेगी और सफाई होगी । बस यही

मेरा आप से नम्र निवेदन है । आशा है सरकार मेरे इन सुझावों पर अवश्य ही ध्यान देगी । जय हिन्द ।

श्रीमती करतार देवी (कलानौर–एस ० सी ०) : आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, सदन के सामने जो सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेट्स के लिये डिमांडज हमारे वित्त मत्री महोदय ने रखी हैं, मैं उन सब का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । मैं डिमांड नम्बर 4, 10,13 व 17 के बारे में अपने सुझाव रखना चाहती हूं । जहां तक डिंमाड नम्बर 4 व सम्बन्ध है उस के पहले पार्ट में बाढ़ नियन्त्रण के लिये सरकार ने जो–जो कार्य किये हैं, वे सचमुच ही बड़े सराहनीय हैं । इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी । चीफ मैं रोहतक खिने से सम्बन्ध रखती हूं इसलिये इस मारे में कुछ कहना अपना कर्तव्य समझती हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, रोहतक जिला सारा ही बाढ की लपेट में आ जाता था । रोहतक प्रौपर में पले थोड़ी सी बरसात में ही इतना पानी भर जाता था कि आना जाना बन्द हो जाता था लेकिन अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और सरकार की वो यह मांग है, उस मांग के तरत के बची किया गया है, वह विद्युत जायज है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक किसानो को जमीन का मुआवजा देने का सम्बन्ध है, इस मरे में सरकार ने काफी ठोस कदम उठाये है, यह बडी ही खुशी की बात है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान के पास सिवाये जमीन के और कोई कमाई का साधन नहीं होता । इस को देखते हुए सरकार ने

काफी अच्छा प्रावधान किया है । मुआवजे की दरें काफी अच्छी हैं और जब तक मुआवजा नहीं दिया आता तब तक सरकार उस जमीन का कब्जा नहीं लेती । अगर इस प्रोसीजर को और भी सिम्पलीफाई कर दिया आए तो लोगों को काफी राहत मिलेगी । लोग कोर्ट में जाने से बचेंगे जिससे लोगों का समय भी नष्ट नहीं होगा और सरकार पर भी कोई बोझा नहीं पड़ेगा । मेरा कहने का मतलब यह है कि जमीन एक्वायर क्रने कैं प्रोसीजर को सिम्पलीफाई किया जाना चाहिये । अगर जल्दी ही इन केसिज को न निपटाया जाए तो हो सकता है उतनी देर में और आर्थिक संकट सरकार के सामने आ जाएं । पहली वाली स्कीम धरी की धरी रह जाए और जो स्वीकृत प्रोग्राम्ज हैं वे पैंडिंग रह जाएंगे जैसाकि मेरे यहां एक बस स्टैड का मामला लगातार डेढ़ साल से पैंडिंग पड़ा है । साईट सिलैक्शन कमेटी उस साईट को देखकर आयी थो । उन्होंने कहा था कि यहां पर बस–स्टैड बनाया जा सकता है । दफा 4 का नोटिस भीं हो चुका णै लेकिन मैं लगातार पिछले डेढ़ दो सालों से यह कोशिश कर रही हूं कि यह कार्यवाही जल्दी ही. पूरी हो जाए । वहां पर जमीन देने वालों को कोई एतराज नहों है । काफी देर से दफा 4, 6, 7 व 9 के नोटिस जारी हो रहे हैं, इस तरह दो साल का समय निकल गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मेरो आपके माध्यम से सरकार दने दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, इस काम को पूरा किया जाए और जो–जो फारमैलिटीज रहती हैं,

उनको पूरा करवाया जाए ताकि लोगों को थोडी सी राहत मिल सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 10 जोकि डा० नसीब सिंह धूल की बहाली और उसको वेतन देने से सम्बन्धित है, पर अपने विचार रखूंगी । वैसे तो न्यायालय का आदेश सरकार को मानना ही होता है लेकिन इससे एक बात की लोगों में शंका उत्पन्न होती है कि रूल की उल्लंघना करके लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है । कोर्ट के आर्डरों के बाद जब तहकीकात होती है तो नही अफसर जिन्होने पहले गल्त राय दी थी, उस केस की पैरवी करते हैं और कह देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये था । इसलिये मेरा शुक सुझाव है कि ऐसे मामलों में हमारे एल० आर० साहब पहले हो अच्छी तरह से छानबीन कर लिया करें ताकि इस कैस की तरह सरकार को बाद में बिना काम करवाये लोगों को इतना कम्पैन्सेशन न देना पड़े । अगर किसी को सजा देनी ही हो तो उसे सर्विस से बर्खास्त करने की बजाये छोटी– मोटी पनिशमैन्ट दे दी जाए तो ठीक रहेगा । अब मैं डिमांड नम्बर 13 जोकि सोशल वैलफेयर से सम्बन्धित है, के बारे में कहना चाहूंगी । 1973 में गांव बोहर, जिला रोहतक 'में स्वतन्त्रता सेनानी स्मारक के निर्माण के लिये सरकार ने भूमि अर्जित की थी । लेकिन जमीन का मालिक सरकार द्वारा दिये गये कम्पैनसैशन से सन्तुष्ट नही था, इसलिये वह अपर जिला न्यायधीश, रोहतक के न्यायालय में अपील में चला गया । उस कोर्ट ने भी उसके मुजावजे की दर

बढा दी । वह उमा मुआवजे से भी सन्तुष्ट न हुआ और हाई कोर्ट में चला गया । हाई कोर्ट ने भी उसके मुआवजे की दर और बढ़ा दी लेकिन वह उस अवार्ड से भी सन्तुष्ट नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में चला गया । सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका मुआवजा बड़ा दिया जिस वजह को सरकार को असली मुआवजे से उसको कई गुना ज्यादा मुआवजा देना पड़ा । अगर पहले से हो मुआवजा देते समय मार्किट वैल्यू का पता कर लिया होता तो इतनी बड़ी राशि सरकार को न देनी पड़ती । अब मेरी सरकार मे रिक्वैस्ट है कि चूंकि सरकार नें अब कानून में परिवर्तन कर दिया है, इसलिये जिस परपज के लिये जमीन एक्वायर की गयी थी, वह जल्दी ही पूरा किया जाना चाहिये । अगर सरकार ने स्मारक वनाने का वायदा लोगों से किया था तो अवश्य ही इस को पूरा किया जाना चाहिये और स्वतन्त्रता सेनानियों जैसा कि रत्ती राम जी हैं, जिनकी मौत जेल में ही हो गयी थी उनके नाम से भी स्मारक बनाया जाना चाहिये । इस बात का हमें 1973 मे पता चला कि सरकार बोहर के अन्दर इस तरह का स्मारक बनाना चाहती है । इनके लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देती हूं कि इस तरह के स्मारक अवश्य ही बनाये जाने चाहियें ताकि लोगों को स्वतन्त्रता सेनानियों की याद ताजा रहे ।

डिप्टी स्पीकर साहब, बडे कुड की बात है कि गांव कूलाहेड़ी के हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है । एक स्कीम के तहत हरिजनों को दो हजार रुपया दिया जाता है ताकि वे अपनी

जरूरत के मुताविक जमीन खरीद लें । जमीन खरीदने के लिए तो ध्याना दे दिया गया लेकिन दुख की बात यह है कि हरिजनों को टाईम पर पैसा न दिये जाने के कारण ब्याना भी जब्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट तक भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई । यह ठीक है त्हि कानून में यही व्यवस्था है । हम लिख कर देते हैं कि अगर इस टाईम तक रजिस्ट्री नहीं करवाई तो ब्याना जब्त हो जाएगा लेकिन यह बगना हरिजनों ने खुद नहीं दिया था । हमारे डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर अधिकारी के माध्यम से यह सारा काम एग्जीक्यूट किया जाता है । उस अधिकारी ने ब्याना देते वक्त यह जानकारी हासिल नहीं की थी किं जिस मालिक को वह व्याना दे रहा है वास्तव में जमीन उसकी है या नहीं । यह केवल कुलाहेड़ी गांव में नहीं हुआ बल्कि जीन्द के अन्दर ढाणी में भी ऐसा ही केस हुआ है । उसमे तो दो कदम और भी आगे बढ़े हैं । इस केम में गवर्नमैंट ने गारन्टी भी दी और मालिक को बैकों से कर्जा लेकर भी दिया । अन्त में जाकर पता चला कि मालिक ने वही जमीन हरिजनों को बेच दी जिसकी वजह से हरिजन अभी तक उस जमीन के मालिक नहीं बन पाए हैं । पहले कैस के बारे में इस किताब में लिखा है कि हरिजनों को जमीन का कब्जा 1964 में दिया गया था और मालिकों के हक में फैसला 1981 में हुआ । इस बारे में सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट पता करे कि अगर गिरदावरी उनके नाम थी तो वे लोग बेदखल किस तरह से हो गए? मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि यह स्कीम बहुत अच्छी थी क्योकि गांवों में जो हरिजन बस्ते हैं वे बेचारे पशु

पाल कर ही अपना गुजारा करते हैं । जो कुछ पड़े लिखे हैं वे बेरोजगारी की वजह से बेकार हैं इसलिये वे पशु पात्र कर ही गुजारा करते हैं । कई– बार इन लोगों के नाथ राजनैतिक कारणों से भी ज्यादती की जाती है । हरिजन लोग जमींदारों की आशाओ के मुताबिक अपना वोट न डालें तब भी उनको परेशान किया जाता है । जैसे एक जगह कोई जमींदार चाहता है कि हरिजन लोक दल को वोट डालें, अगर वे कांग्रेस को डाल देते है तो इस बजह से उनका बाई काट कर दिया जाता है । उनको कहा जाता गै कि आपको खेतों में से नहीं निकलने दिया जाएगा । फेम वजह सै उनको अपने पशुओं के लिए चारा लाने की दिक्कत आती शै । इसलिये सोशल वैलफेयर विभाग कोई ऐसी स्कीम रखे जिसके तहत उनको दो–दो एकड़ जमीन दी जा सके । ऐसी स्कीम चाहे सामूहिक तौर पर जमीन देने की हो या इंडिविजुअल तौर पर देने की हो, जरूर रखें । अगर ऐसा हो जाता है तो वे लोग भी अपनी वोटो का अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं । अब तो भूमि विकास बैकों ने भी षज देने शुरू कर दिए है । अच्छा होगा अगर समाज कल्याण विभाग उनकी हुछ मदद करे । यह जो पैसा मांगा जा रहा है यह दिया जाना तो ठीक है क्योंकि जो व्याना जब्त हुआ है वह सरकारी अफसरों ने दिया था इसलिये सरकार को ही यह बहन करना पड़ेगा । आज समाज कल्याण विभाग लोगों की जिन्दगी के साथ पूरी तरह जुडा हुआ है । महिलाओं, विकलांगों और वृद्धों को पैन्शन देन की स्कीम काफी समय मे

चालू है । लेकिन लोगों मे भ्रांति शै कि सात्र–साल भर उनकी दर्खास्तें पड़ी रहती हैं और उसके बाद औवजैकशन अगा दिया जाता है किं आपकी दर्खास्त पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही है । इस बारे मे मेरा सुझाव है कि जिला स्तर पर उनको फार्मों की स्क्रूटनी पहले ही हो जाए कि क्या–क्या कमी है । उस कमी को दूर करवा कर पैन्शन पाने योग्य लोगों को शीघ्र पैन्शन दे दी जाए । आगे के लिए ऐशा होना चाहिए कि एक स्पैशल कम्पेन चला कर सभी विधायक या सभी सोशल वैलफेयर अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र से योग्य व्यक्तियों की दर्खास्तें ले ले और सरकार उनको समय पर पैन्शन दे दे ताकि किसी कौ भी इन गरीब लोगो की मजबूरी का फायदा उठाने का मौका न मिले । इन शब्दों के साथ जो इन चारों डिमांडज में पैसा मांगा गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो डिमांडज हमारे वित्त मन्त्री जी ने रखी है मे उनका समर्थन करता हूं । डिमांड नं० 10 पर बोलते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार का तीस हजार की आबादी पर प्राइमरी हैल्थ सैंटर खेलने रहा प्रावधान है । मेरे हल्के में भी कुछ ऐसे गांव हैं जहा मे मन्जूर तो हो गए हैं लेकिन अभी तक इनका काम शुरू नहीं हुआ है । जैसे सदन हेडी गांव है, भाटोल है और आलमपुर गांव है । सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है थि गांवों में लोगो के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राइमरी हैल्थ सैटंर्ज खोले जाएं ताकि गांव

के लोगों को चल कर शहरों में इलाज करवाने के लिए न जाना पड़े । दरकार ने यह अच्छी स्कीम चलाई है । इसलिये मैं यह चाहुंगा कि जैसे और जगह यह सैटर्ज खोलने की बात है, उसी तरह से मेरे हल्के में भी ये जल्दी से जल्दी खोले जाएं । कई गांवों में हस्पताल भी हैं लेकिन स्टाफ नहीं है । जैसे उमरा गांव है, बहां हस्पताल तो है लेकिन डाक्टर नदी है । इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां जहां स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करके सरकार लोगों को लाभ पहुंचाए । इन शब्दों के साथ मैं इस डिमांड का समर्थन करता हूं । डिमांड नं ० 17 कृषि के बारे में है । आज तो ग्रामीण बैक खोले जा रहे हैं उनके अन्दर हरियाणा सरकार अपना हिस्सा डाल रही है । इसके लिए 11, 25,000 रुपए मांगे गए हैं । यह अच्छी स्कीम है कि ये बैक गांवों के लोगों को छोटे–छोटे कर्जे देकर उनके कारोबार में काफी मदद करते है । लेकिन इस काम में कुछ कमियां भी है जिस वजह से लोगों को परेशानी होती है । इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां सरकार इन बैकों को अपने हिस्से की राशि देती है, वहां इन पर वह अपना कन्ट्रोल भी रखे ताकि लोगों को किसी किस्म की तंगी न हो । डी ० आर ० डी ० ए ० की मार्फत भी लिखा जा सकता है कि फलां–फलां आदमी को लोन दिया जाए । ऐसा करने से लोगों की काफी सहुलियत रहेगी । डिमांड नं० 13 सोशल वैलफेयर के बारे में है । जैसे मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी बताया कि 155 एकड़ जमीन जो फतेहाबाद तहसील में ली गई उसका व्याना इस वजह से जब्त हो गया कि ही रजनों को बैकों से बाकी रुपया देने

के लिए नहीं मित्रा जिस वजह से जमीन के मालिक ने अदालत में दावा दायर करके जमीन वापिस ले ली । इसलिये पहले ही अगर इस बारे में सारी कार्यवाही हो जाती तो यह मामला अदालत में न जाता । कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि पहले ही मालिक से बातचीत करके उस इलाके में जमीन का जो भाव है उस भाव पर उसको पैसे दे दिए जाएं तथा इकरारनामा लिखा लिया जाए कि वह अदालत में नहीं जाएगा, उसको यह भाव मंजूर है । अदालत मैं आने से पहले ही निर्णय लेना चाहिए, यह अच्छा है । इसके अलावा, अभी थोड़ी देर पहले बहन जी पैशन के बारे में वहुत कुछ बोली हैं । डिप्टी स्पीकर साहब हांसी रेलवे स्टेशन के पास एक सौ से भी ज्यादा अपाहिज रहते हैं और वे पिछले कई सालो से यही रह रहे हैं । मैंने कई बार उनके बारे में सरकार को लिख कर भी दिया है कि उनके रहने के लिए कोई कालौनी बना दी जाये । वे लोग वहां पर कई सालों से डेरा डाले हुए हैं । अब वे वहीं के बाशिंदे बन चुके हैं । उनमें से किसी के हाथ नही हैं किसी के पैर नहीं हैं और कई बिल्कुल अपाहिज हैं । ये भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं लेकिन भीख मांगने पर सैटर गवर्नमैंट ने एक एक्ट बना कर पाबंदी लगा रखी है जिसके तहत हरियाणा सरकार ने उनको पकड़ कर केल में बंद कर दिया था । जब वे जेल से छूट कर आए तो कहते हैं कि या वो हमारे लिए रोटी का प्रबन्ध किया जाए या हमें पैशन दी जाये क्योंकि हमारे पास भीख मांगने के सिवाय दूसरा कोई धंधा नहीं हूं । इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐंमें अपाहिजों को पैशन दने

का जल्दी से जल्दी प्रावधान किया जाये ताकि ये अपना गुजारा कर सकें । जो अपाहिज हैं वे अपनी रोटी कमाने में बहुत मजबूर हैं, वे कोई काम नहीं कर सकते हैं । इसलिए जिन अपाहिजों कौ सरकार पैशन दे रही है उनको समय पर पैशन मिल जानी चाहिए और जिन्होंने पैंशन के लिए सरकार को प्रार्थना की हुई है, उनको जल्दी पैशन मिल जानी चाहिए । जो देरी वाली बात है उसको बीच में से हटा कर कोई ऐसा सिस्टम लागू करें जिसके जरिए अधिकारी मौके पर ही उनके फार्मों की जांच करके ठीक कर सकें । इस समय उनको डाक्टर और तहसीलदार के दस्तखत करवाने –पड़ते हैं लेकिन फिर भी किसी न किसी कमी के कारण उनके फार्म वापिस ढ़ग जाते हैं । डाक्टर और तहसीलदार के साइन होने के बाद भी बहुत कमियां रह जाती है जिनके कारण उनके फार्म वापिस आ जाते हैं । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार यह काम डिप्टी कमिश्नर या समाज कल्याण अधिकारी के जिम्मे लगाए, वह मौके पर जा कर उनके फार्मों को जांच करके ठीक कर दें ताकि उनको पैशन ठीक समय पर मिल जाये । यदि पैंशन ठीक समय पर मिल जाए तो वे परेशानी से बच सकते हैं । इनके अलावा, 'मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि कई गांव ऐसे हैं जिनमें हरिजन चौपाले अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा करवाया जाये । उन गांवों के गरीब हरिजनों के पास पैसे नहीं है लेकिन गांव की पंचायत ने चौपाल बनाने के लिए जमीन दी हुई है । पैसा न होने के कारण चौपाल नही बनाई जा सकी है । गरीब हरिजनों को शादी–गमी में बैठने के लिए जगह चाहिए । इसलिए मैं सरकार से

प्रार्थना करूंगा कि जिन गांवों में हरिजन चौपालें नही हैं या अधूरी पड़ी हैं, उनको जल्दी से जल्दी बनाया जाए । मेरे हल्के में सिंगवा और गढ़ी गांव हैं जिनके अन्दर हरिजन चौपाल नहीं है । पिछले दिनों श्री फूल चन्द जी वहां पर गए थे इन्होंने वहा पर 25 हजार रुपए चौपाल के लिए देना अनाउंस किया था लेकिन वह पैसा अभी तक नहीं मिला है । इसी तरह से गांव उमरा है, ढाणी पाल है, इन गांवों की हरिजन चौपालें अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा करवाया जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन डिमांडज का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन (बरवाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, इन डिमांडज के जरिए जो पैसा मांगा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं डिमांड नम्बर 4, 10, 17 पर बोलना चाहूंगा । सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर 4 जो रैवेन्यू से ताल्लुक रखतीं है और इस डिमांड के जरिए जो पैसा मांगॉ गया है यह जायज है । यह पैसा देना ही चाहिए लेकिन इसके बारे में मैं अपरने हल्के की कुछ बातें कहना चाहूंगा । बरवाला मेरा हल्का है और उसकी आबादी 40 हजार के लगभग है। वहा पर पंचायत समिति और दूसरे वहुत से औफिसिज हैं । मैं पहले भी कई बार सरकार से माना कर चुका हू और आज फिर उस बात को दोहराता हूं कि बरवाला को तहसील बनाया जाये । बरवाला को तहसील बनाने के लिए पूरी जस्टीफिकेशन बनती है । डिप्टी स्पीकर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार नीचे से केस रिकमैड

करके भेजा है कि इसको तहसील बनाया जाये । बरवाला अकेला हल्का नही है । ईसके साथ लगते हुए धिराये, भट्टू और नारनौंद हल्के भी हैं और बरवाला से 30– 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई तहसील भो नहीं हैं । उधर हिसार लगता है, दूसरी तरफ टोहाना लगता है और इधर जींद लगता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बरवाला को तहसील बनाने की जायज मांग है और वहां के लोगों की तरफ से यह बहुत दिनों से मांग चली आ रही है । इसकॉ लोगों को बड़ी भारी जरूरत है इसलिए सरकार बरवाला को तहसील बनाने के लिऐ कंसिडर करे ताकि वहां के लोगों को लाभ हो सके । इससे आगे मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें पब्लिक हैल्थ की डिमांड नहीं है ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें दे रखी है । वैसे तो यदि आप बोलने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा । मैं ज्यादा स्ट्रैस नहीं करूंगा इसमें पब्लिक हैल्थ के बारे में दिया हुआ है । डिप्टी स्पीकर साहब, पानी और हवा की इन्सानी जिन्दगी के लिए बहुत जरूरत होती है । पीने के पानी के बारे में हरियाणा सरकार ने बहुत काम किया है उसके लिए मैं सरकार का बहुत– बहुत धन्यवाद, करता हूं क्योंकि हरियाणा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसने पीने के पानी की सुविधा लोगों को सबसे ज्यादा दी हुई है । मैं अपने गांव हसनगढ के बारे में सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा । मेरा हसनगढ गांव है, वहां पर

ओवरहैड टैंक नहीं है । उसके साथ तीन गांव जुड़े हुए हैं, उसके लिए सरकार ने पैसा भी अलाट कर दिया है, उस पर जल्दी काम शुरू करवाया जाए । मेरी सरकार से यही प्रार्थना इसके अलावा डिमांड नम्बर 17 जो एग्रीकल्चर के बारे में है, पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा । वैसे तो सारा हिन्दुस्तान ही कृषि प्रधान देश है और हरियाणा भी उसी आधार पर कृषि प्रधान प्रदेश है । डिप्टी स्पीकर साहब, जो मार्किट कमेटियां हैं, इनके बारे में यह फैसला हुआ था कि इनकी इनकम का 40 परसैंट पैसा पी ० डब्ल्यू ० डी ० के पास जमा किया जाए । चौधरी अमर सिंह जी सदन में बैठे हुए हैं, उस समय वे पी ० डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर होते थे । वह पैसा बरवाला और उकलाना की मार्किट कमेटियों ने सरकार की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जमा भी करवा दिया था । यह पैसा उनके पास देहात से आता है । उस पैसे से जो सड़कें बनाई जाती हैं वे मार्किट कमेटियों की डायरैक्शन के मुताबिक बननी चाहिएं । जो सडकें मार्किट कमेटियों की डायरैक्शन से बनती है, उनको बनाने में प्राथमिकता दी जाये ताकि वह पैसा देहात की सड़कें बनाने पर खर्च हो । वह देहात का ही पैसा है इसलिए देहात की सड्कों को बनाने पर ही खर्च हो, उस का सदुपयोग हो । यह मेरी सुजैशन है । इतनी बात कह कर मैं इन डिमांडज का समर्थन करते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

चौधरी अजमल खां (नूह) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज हाउस के सामने 4 मांके हैं जिन परं' मैं बोलना चाहूंगा । मेरे से

पहले बोलने वाले मेरे साथी इन पर काफी रोशनी डाल चुके हैं । रैवेन्यू के बारे में यह बात आम थी कि किसान को बाढ से हुए नुकसान का जो 400 रुपये मुआवजा दिया जाता है, वह बहुत कम है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह तो किसानों के साथ एक मजाक है । आज के जमाने में 400 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है । इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और इस राशि को और बढाया जाना चाहिए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हैल्थ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । सरकार हैल्थ के काम कर रही है और हाउस से इन मांगों के जरिए पैसा भी मांगा जा रहा है । मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हैल्थ के लिए पैसा दिया जाना चाहिए । लेकिन साथ साथ यह भी अवश्य होना चाहिए कि हैल्थ के जो काम हों, वे दिखाई देने चाहिए । सरकार द्वारा हस्पताल बनाये जा रहे हैं लेकिन मेवात के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर हैल्थ का कोई काम होता नजर नहीं आता । जो हस्पताल पहले के बने हुए हैं उनके लिए भी स्टाफ नहीं है । सरकार की पालिसी के मुताबिक 30 हजार की आबादी पर एक पी० एच० सी ० खुलना चाहिए लेकिन हमारे इलाके में 30 हजार की आबादी पर तो क्या, 50 हजार की आबादी पर भी कोई पी० एच० सी० नहीं है और न ही सरकार ने अपनी पालिसी के मुताबिक वहां पर कोई जमीन वगैरा ही एक्वायर की है और न ही कोई नई बिल्डिंग आदि बनाई

है । जो काम हैल्थ के हो रहे हैं वे हमारे इलाके में नहीं हो रहे बल्कि दूसरे हल्कों में ही हो रहे हैं । मैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यही कहूंगा कि शायद सरकार का ध्यान हमारे हल्के की तरफ नहीं है । मेरे अपने गांव में 4 साल पहले एक हस्पताल की बिल्डिंग बनी थी । वहां पर कुछ समय के लिए तो एक स्टाफ नर्स आई थी । यदि वहां पर स्टाफ नहीं दिया जायेगा तो वे सारी बिल्डिंगे जो बनाई हुई भी हैं, बेकार हो जाएंगी 1 दूसरे, जब कोई वहां पर नहीं रहेगा तो लोग उन बिल्डिंगों से इंटें भी उखाड़ कर ले जाएंगे और वह बिल्डिंगें बिछल बेकार हो जाएंगी । इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां पर बिल्डिंगें बनाई हुई हैं वहां पर पूरा स्टाफ दिया जाये ताकि वहां के रहने वालों को फायदा हो सके । फैमिली प्लानिंग की स्कीम के तहत जो बिल्डिगें बनाई जानी थीं, वे भी मेरे हल्के में नहीं बनाई गई है । सरकार को हर इलाके की तरफ ध्यान देना चाहिए । दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मिनिस्टर्ज के पास जितनी ग्रान्टस होती हैं वे अपने अपने हल्कों में बांट देते हैं, दूसरे हल्कों में उस ग्रांट का पैसा नहीं देते । इस बारे में मेरा सुझाव है कि ऐसी ग्रान्टस सारे हल्कों में बराबर बराबर बांटी जानी चाहिएं । यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हरियाणा के एक हिस्से में तो विकास हो जायेगा लेकिन दूसरे हिस्से से बदबू आयेगी । इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार फौरी तौर पर हैल्थ का काम सभी जगहों पर समानता के साथ करे और सरकार की पौलिसी के मुताबिक जो 30 हजार की आबादी पर एक पी० एच० सी० होना चाहिए, वह हर जगद खोला

जाना चाहिए । सरकार जगह जगह पर फैमिली प्लानिंग के कैम्प लगा कर उन पर लाखों रुपया खर्च करती है । इस बारे में मेरा कहना यह है कि इस स्कीम से जितना फायदा लोगों को होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है । हमारी मातायें और बहनें जो आखों से अन्धी हैं, उनको डी ० सी० आफिस, सी० एम० ओ० आफिस व बी ० डी ० ओ० आफिस में ले जाया जाता है जिनसे उन्हें बड़ी भारी परेशानी होती है । इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि ऐसे कैम्प कस्बों में लगाने की बजाये आसपास के गांव में लगायें जाएं ताकि उनको दिक्कत न हो सके और वे सही लाभ उठा सकें । अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो हमारे ऊपर जो हमारे बुजुर्गों का बोझ है, उसको ठीक प्रकार से निभा सकेंगे । अब मैं कृषि से संबंधित मांग पर बोलना चाहूंगा । इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के लिए पानी बहुत जरूरी है । कृषि को पानी देने के लिए अलग से डिपार्टमैंट है । इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि विभाग को अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसानों को ठीक समय पर पानी मिल सके । कृषि विभाग किसानों को यह जानकारी दे कि कौन से समय पर कौन सा बीज बोया जाना चाहिए और कितनी माला में खाद डाला जाना चाहिए । जो बीज जिस समय बोया जाना होता है, वह उसी समय किसानों को दिया जाना चाहिए । यदि संबंधित बीज को जैसे डब्ल्यू० 47 है, 1553 है या 1540 है, अगर समय पर किसानों को नही दिया जायेगा और उसको तिथियों से आगे पीछे बोया जायेगा तो उतनी ही उस

बीज की पैदावार कम होगी । इसलिए मेरा कृषि विभाग को सुझाव है कि जो भी बीज किसानों को दिया जाये, वह समय पर दिया जाये और समय पर खाद पहुंचाया जाना चाहिए ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो सके । खाद के बारे में मेरा सुझाव है कि इस पर सबसिडी किसानों को दी जानी चाहिए क्योंकि बीज तो किसान अपने पड़ौसी से भी लेकर डाल सकता है । यदि समय पर किसान को खाद नहीं मिलेगा तो वह इधर उधर से लेकर डाल देगा और उसे सरकार द्वारा जो खाद पर सबसिडी मिलनी चाहिए, वह उसे नहीं ले पाता । इ ससे किसान को नुकसान होता है । ऐसा न होने पर जो ठेकेदार हैं वे उस खाद को वहां के किसानों की बजाये, यू ० पी० या राजस्थान में बेच देते हैं । यह बात मेरे हल्के में आम है । वहां पर अभी तक खाद व बीज सही समय पर नहीं पहुंचाये गए हैं । इस बारे में मेरा सुझाव है कि कृषि विभाग को किसानों को सारी जानकारी सही समय पर देनी चाहिए । एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि किसानों के टयूबुवैल्ज का जो पानी या मिट्टी टैस्ट की जानी होती बै, उसे कृषि विभाग के कर्मचारी ही लेकर जायें और वे ही उस सैम्पल की रिपोर्ट किसानों को लाकर दें ताकि किसानों को रिपोर्ट के लिए भाग दौड़ न करनी पड़े । अगर सरकार सारी सुविधाएं किसानों को प्रदान करेगी तो उत्पादन भी अधिक बढ़ सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं इन डिमाण्डज का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

मास्टर राम सिंह (रादौर, अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इन डिमान्डज पर बोलने के लिए समय दिया । मैं डिमान्ड नं ० 4, 10, 13 और 17 पर बोलना चाहूंगा । सबसे पहले मैं डिमांड नं ० 10 जो हैल्थ से संबंधित है, पर बोलना चाहूंगा । इस डिमांड के जरिए सरकार हैल्थ का काम करने के लिए पैसे मांग रही है । सरकार की पालिसी के मुताबिक 30 हजार की आबादी पर एक पी ० एच० सी० होना चाहिए । मेरा हल्का रादौर है । रादौर में तो एक पी० एच० सी० है लेकिन जो साथ लगता एरिया खादर का है, जिसकी आबादी 30 हजार से कहीं ज्यादा है, वहां पर कोई पी० एच० सी० नहीं है । खादर का जो पानी है, वह क्षत खराब है जिसकी वजह से वहां के लोग बाय के दर्द से और दूसरे दर्दी से काफी परेशान हैं । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि खादर के एरिया में एक पी ० एच० सी० अवश्य खोला जाये ताकि लोग बीमारियों से बच सकें । रादौर में जो हैल्थ वैल्फैयर सैन्टर की बिल्डिंग है, वह 4– 5 साथों से बन रही है लेकिन अभी तक पूरी कम्पलीट नहीं हो पाई है। इस बारे में मैंने कई बार मंत्री जी को वताया भी है । वहां का जो ठेकेदार है, वह ठीक काम नहीं कर रहा है । उस ठेकेदार पर पैनेल्टी भी लगाई जा चुकी है । दूसरे वहां पर जो सर्वेन्ट क्वार्टर्ज हैं, वे भी नहीं बनाये गए हैं । इस बारे में मेरा सुझाव है कि वहां पर जल्दी से जल्दी सर्वेन्ट क्वार्टर्ज बनाये जायें ताकि लोगों को कोई दिक्कत न आये । इस समय सर्वेन्ट क्वार्टर्ज न होने के कारण वहां से कर्मचारी दूर जा कर

रहते हैं जिसकी वजह से लोगों को अपने इलाज के लिए काफी परेशानी है । दवाइयों की भी बहुत बुरी हालत है । लोगों को वहां से दवाइयां नहीं मिल पातीं । उन्हें सारी दवाइयां बाजार से लेनी पड़ती हैं । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज को काफी माता में दवाइयां देने का प्रावधान किया जाए ।

12. 00 बजे ।

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं ० 13 सोशल वैलफेयर एंड रीहैबिलिटेशन की है । इसके बारे में मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जिन चौपालों का काम 4– 5 साल पहले शुरू हुआ था और अभी इनकम्पलीट पड़ी हैं, उनका काम सबसे पहले खत्म करवाया जाए । बहुत सी चौपालें ऐसी हैं जिन पर छत नहीं डली है । डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूं कि जिस चौपाल का उद्घाटन आपने किया था उसका काम नींव से ऊपर नही हुआ है । तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसी चौपालों की कम्पलिशन के लिए सरकार को बजट में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, वैलफेयर डिपार्टमैंट जो ओल्ड एज पैन्शन देता है उसमें भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है । कई बूढ़े बुजुर्ग और स्त्रियां पैन्शन के फार्म तो भर देते हें लेकिन उनको कई साल तक पैन्शन नहीं मिलती । पैन्शन का

तरीका ऐसा बनाया जाए कि फार्म लेते ही उनको जवाब दिया जाए और एक महीने के अन्दर अन्दर उन्हें पैन्शन लग जानी चाहिए । आज पैन्शन का तरीका ऐसा बना हुआ है कि तीन तीन महीने, छः–छः महीने और कई बार नौ–नौ महीने पैन्शन मिलने में लग जाते हैं । वे लोग फिर एम० एल० एज० के पास आते हैं । इसमें हम भी क्या कर सकते हैं जब तक पैन्शन का तरीका ठीक न हो । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पैन्शन का तरीका ऐसा बनाया जाए कि एक तो यह जल्दी से जल्दी सैक्शन हो जाए और दूसरे या तो हर महीने पैन्शनर्ज को पैन्शन मनीआर्डर द्वारा मिलती रहे या तीन–तीन महीने के बाद रैगुलरली मिलती रहे ।

डिमांड न ० 17 ऐग्रीकल्चर की है । हमारे जिला कुरुक्षेत्र में लगभग 75,000 ट्यूबवैल्ज हैं । इतने ज्यादा ट्यूबवैल्ज बाकी हरियाणा के अन्दर नहीं हैं । जी० टी० रोड का जो उत्तरी हिस्सा है उसके अन्दर सिवाय ट्यूबवैल्ज के इरीगेशन का कोई और साधन नहीं है । इसाका मेरे ख्याल में जितने ट्यूबवैल्ज मेरे हल्के में है उतने शायद सारे हरियाणा में नहीं हैं । इस वजह से मेरा निवेदन है कि वहां ऐग्रीकल्चर को बिजली देना बहुत जरूरी एं ताकि वहीट की बुआई के समय उन्हें कोई दिक्कत न हो और वे ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर सकें । आज हालत यह शै कि बबैन एरिया में कमी भी लगातार 6 घंटे से ऊपर बिजली नहीं आती । वे लोग इस कारण बड़े परेशान हैं । वे हमेशा यही कहते हैं कि पता नहीं क्यों चारों तरफ से हमारी बिजली काट दी जाती

है । कई बार शाहबाद से बिजली काट दी जाती है और कई बार पिपली से बिजली काट दी जाती है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर जो सबस्टेशन्ज हैं उनको अपग्रेड किया जाए । मैं तो यी भी मांग करूंगा कि बबैन और लाडवा को गिरी–बाटा पावर हाउस से फौरन जोड़ने का प्रावधान किया जाए । इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांडज का समर्थन करता हू और आशा करता हू कि मेरे हल्के की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा । (इस समय भी अध्यक्ष पदासीन हुए ।)

चौधरी सूबे सिंह पुनिया (उचाना कलां) : स्पीकर महोदय, अनुपूरक मांग नं ० 4,10,13 और 17 जो हाउस के नामने क्यो गई हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं । प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुक्सान से राहत दिलाने के लिये राजस्व मांग के अन्तर्गत जो पैसा जुटाया गया वह बहुत ही जरूरी या । स्पीकर साहब, जिन इलाकों में बाढ़ आती है या सूखा पड़ जाता है, उनमें मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये, बच्चे। के स्वास्थ्य के लिये, पशुओं के स्वास्थ्य के लिये तथा इस बात की रोकथाम के लिये कि वहां कोई महा– मारी न फैल जा, इस तरह पैसे का इन्तजाम करना बहुत जरूरी होता है । फिर छोटे और सीमान्त किसानो के लिये भी सहायता जुटाई गई हैं । बाढ़ आने से जो सडकें टूट जाती हैं या खराब हो जाती हैं उन पर मिट्टी डाली जाए तथा उन्हे ठीक किया जाए यह भी बहुत जरूरी था । इसके अलावा बिजली की संचार व्यवस्था में जो कमी आ जाती है उसको ठीक करना भी

बहुत जरूरी होता णै । लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है । जहां बाढ आती है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं या ओलावृष्टि होती है वहां पर गांव को, क्षेत्र को या जिले को ईकाई न मानकर उस. जगह को या खेत को ईकाई माना जाए, नुक्सान को आका जाए और सम्बन्धित किसानो को मदद दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मांग नं ०10 मैडिकल एंड पब्लिक हैल्थ के सम्वन्ध में हैं । मनुष्य यदि स्वस्थ हो तभी कुछ कार्य कर सकता है । इस पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान रखा गया है कि 30 हजार की आबादी पर एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर खोला जाएगा लेकिन इस बारे में भी मेरा एक सुझाव है । आज स्थिति यह है कि जहां पर प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज हैं या सब सैन्टर्ज हैं उनमें अभी तक पूरा स्टाफ नहीं है । उनमें पूरा स्टाफ भेजने के बाद ही नए प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज या सब–सैन्टर्ज खोले जाने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं लोक स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं । आज हालत यह है कि फिरनियो के बाहर भी गांव फैल गार है और पब्लिक हैल्थ के स्टैण्ड पोस्टस फिरनियो के अन्दर आ गए हैं । वहां सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं है । हालत इतनी बुरी हो गई है कि वहां मनुष्य का स्वयं और बैलगाड़ी के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो गया है । उससे बदबू और गन्दगी गली में फैत्र जाती है । मेरा अनुरोध है कि जहां स्टैन्ड पोस्टस फिरनियो के अन्दर आ गए हैं उन्हे वहां से हटाकर या तो गालियों के मोहाने पर लगा दिया जाए या चार पांच

स्टैन्ड–पोस्टस को एक साथ तालाब के किनारे पर लगा दिया जाए या अलग से गड्ढा खोदकर उसमें गन्दगी जाने की व्यवस्था कर दी जाए ताकि बीमारी से बचा जा सके औंर आने जाने में सुविधा हो सके । रेगिस्तानी इलाकों में जहा गलियां कच्ची है वहा तो यह दिक्कत नहीं है लेकिन जहां गलियां पक्की हैं वहां हालत खराब है । वहां इस असुविधा ने वहुत ही उग्र रूप धारण किया हुआ है । वहां गांव की गलियो मे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि अब जो भी नई स्कीम हाथ में लो जाए उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए और गांव में सीवरेज के लिये कोई न कोई व्यवस्था पहले से की जाए ।

स्पीकर साहब, तीसरी जो मांग रखी गई है वह समाज – कल्याण और पुनर्वास के बारे में है । सरकार इस बारे में पहले से ही बहुत प्रोत्साहन दे रही है । वृद्धों और अपाहिजों को पैन्शन काफी माता में दी जा रही है लेकिन इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि जिन वृद्धो के पुत्र या पुत्रियां नही हैं, उन्हें पैन्शन देने में प्राथमिकता दी जाये क्योंकि उन बेचारो का कोई और सहारा नहीं होता है । फैमिली प्लानिंग की वजह से उनकी दशा शोचनीय हो जाती है । इसलिये मेरी सरकारी ' से गुजारिश है कि इस बारे में उन्हें प्राथमिकता दी जाये ताकि उनका गुजारा हो सके । इन शब्दों के साथ मै इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

वित्त मन्त्री (चौधरी कटार सिंह छोकर) : स्पीकर साहब, सप्लीमैंटरी डिमान्डज पर बोलते हुए मेरे साथी विधायकों ने

आमतौर पर डिमान्डज को एप्रूव किया और सराहा भी है लेकिन साथ साथ अपने क्षेत्र की कठिनाइयों का भी जिक्र किया है । जो उन्होंने यहां पर जिक्र किया वह इन डिमान्डज तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि बहुत सी जनरल बातें भी कही हैं । आज उन्हें बोलने का काफी अवसर मिला है इस लिए उनकी सभी बातों को मैंने नोट किया है । हर विभाग को ये हिदायत है कि उनकी मांगों को नोट कर लें और जो भी उचित कार्यवाही हो सकतीं है वह की जाये ।

स्पीकर साहब, सब से पहले श्री भले राम जो बोले थे । उन्होंने ड्रेनो की बाबत कहा किं पिछले सालों में फलड आये हैं । उनके अपने इलाके में भी फलड आया । रोहतक सोनीपत में तो हर साल नहीं तो एक या दो साल के बाद फलड आते रहे हैं जिसके कारण सरकार को अचानक उन पर बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है । उन्होंनें कहा कि सरकार पहले ही इनका पक्का इन्तजाम करे, ड्रेनों को पक्का बना दिया जाये ताकि एकदम से इतना पैसा खर्च न करना पड़े । उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधा सभी इलाकों के लिये पहले ही की जाये ताकि ऐमरजैन्सी मे खर्च न करना पड़े । मैं उनको बताना चाहूंगा कि ड्रेनों के लिये और फलडज के लिये पहले ही हर साल पैसा रखा जाता है । पिछले दो तीन साल से 14 करोड़ और अब 12 करोड़ रुपया रखा गया है । यह भी आप सभी जानते हैं कि फलड हर साल नही आते हैं इसलिये इस पैसे को दूसरी ओर भी डायवर्ट करते रहतै हैं । जैसे

पिछले दिनों एस ० वाई ० एल ० के लिये भी देते रहे हैं । मजबूरी में ही कहीं इस पैसे की डाय– वर्शन करनी पड़ती है । बहुत पहले से, जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री होते थे तभी से फलड कन्ट्रोल बोर्ड बना हुआ है। उसी समय सै लगातार स्कीमें बनती रही हैं । एक विभाग के अन्दर अलग से ड्रेनेज विभाग काम करता है । इन फलड्ज की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है । वैसे हमारे यहां फलड की इतनी प्रौब्लम नहीं है बल्कि ड्रेनों की प्रोब्लम है क्योकि जहां पर फलड का पानी आता है वहां पर कोई नदियों का पानी नहीं आता है । रोहतक, सोनीपत या जीन्द के इलाके में जौ फलड आता है वह बारिश का पानी होता है । वह बारिश का पानी एक इलाके में ठहर जाता है । जमना नदी का जो पानी आता है उसके साथ थोड़ा बहुत फलड आता है । हमारे यहा तो मेन प्रौब्लम ड्रेनेज की है, उसका सरकार की तरफ से पूरा ध्यान रखा जाता है । श्री भले राम जी ने अपने हल्के की दो ड्रेनों का जिक्र किया है कि उन पर काम किया जाये । दूसरे, उन्होंने यह भी कहा है कि कई दफा ठेकेदारों द्वारा किये हुए काम का पैसा नहीं दिया जाता इसलिये उस तरफ भी ध्यान दिया जाये । एक बात उन्होंने डाक्टर की सर्विस टरमिनेट करने के बारे में कही कि किसी की सर्विस टरमिनेट करते समय उसकी चार्ज शीट पर भी ध्यान रखा जाये । उन्होंने कहा कि जो आदमी कोर्ट के माध्यम से सर्विस में आ जाता है वह एरियर भी कलेम करता है । यह बात ठीक शै इस बारे मैं सावधानी बरती जानी चाहिये लेकिन कही न कहीं फला रह ही जाता णै । डाक्टर धूल

के केस में ऐसा ही फला रहा । उसे प्रोबेशन पीरियड में समझ कर उसकी सर्विस टरमिनेट कर दी गई । वैसे उभ पर मौरल टरपिचयूट के चार्ज भी थे लेकिन कोर्ट ने यह प्ली ले ली कि बह प्रोबेशन पीरियड में नही था, वह पीरियड खत्म हो चुका था इसलिये आप उसकी सर्विस टरमिनेट नहीं कर सकते । बार्डर लाईन के ऐसे केसिज में कोताही हो जाती है, आइन्दा सरकार इस बात का ध्यान रखेगी । उन्होने यह भी चाहा है कि ऐसे अधिकारियों की जिस्मे– बोरी ठहरायी जाये जो ऐसै गलत निर्णय करते हैं । मैंने इस बारे में कहा है कि कई दफा ध्यान मे नहीं रहता है और गलती से हो जाता है । उन्होंने यह भी कहा कि जीप के ड्राईवर का नाम भी पता नही किया ऑर सरकार ने कलेम दे दिया । जीप ड्राईवर के बारे मे सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस की किताव में नाम लिखा हुआ है कि किस ड्राईवर से गलती हुई है । उस केस में ड्राईवर की गलती नहीं थी । एक आदमी अचानक आगे आ गया जिसके कारण एक्सीडैन्ट हो गया इसलिये सरकार कों कम्पनसेशन देना पड़ा । उसका हक बनता था इसलिये दे दिया । उन्होंनें यह भी कहा है कि बैकों से लोन देने का प्रोसीजर सिम्पलीफायी किया जाये । वैको से जों लोन मिलता है उसका प्रोसीजर उन्होने काफी लम्बा चौड़ा बताया है । इसमें बात यह है कि बैंकों की अपनी जिम्मेदारी है कि जिसको वह लोन दे, वह देखता है कि वह री–पे करने की स्थिति में है या नहीं । इस तरह से उस जिम्मेदारी को देखते हुए वह कई दफा बौटलनैक क्रियेट कर देता है । कई दफा जब वे कागज पूरे करवाते हैं तो

उसमें लोग परेशान होते हैं । सरकार कोशिश कर रही है कि इस प्रोसीजर को सिम्पल करे । जल्दी से जल्दी मुख्य मती जी सड़ी बैकों की मीटिंग करवा रहे हैं, जितना भी आसान तरीका हो सकेगा दह करवा रहे हैं । सरदार लछमन सिंह ने कहा कि एल ० ए ० ओ ० जानबूझ कर कम्पनसेशन कम देते रहे हैं । वे लैन्ड ओनर को हैरास करते हैं । वे जानबूझ कर एवार्ड कम देते रहे हैं इसलिये उनके खिलाफ कार्य वाही करनी चाहिए । जहां पर यह साबित हो जाये कि वाकई ही उस एल ०ए ०ओ ० ने जानबूझ कर कम एवार्ड दिया है, ऐसा कोई केस हमारे नोटिस में आयेगा तो सरकार कार्यवाही करेगी ताकि लोगों को इस बात से हैरास न किया जाये ।

श्री लछमन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मेरी अर्ज यह है कि फाइनैन्स मिनिस्टर साहके ने जो जवाब दिया उससे मैं मुतफिक नहीं हूं । वह बहुत तसल्ली– बख्श जवाब नहीं है । आप इन सप्लीमैंटरी में देखें कि पहले सरकार ने 78 हजार रुपया जमींदारों को दिया लेकिन जब वे कोर्ट में चले गये तो उन्हें 23 लाख रूपया देना पड़ा । इस बात से ही आप देख सकते हैं कि कोई कम्पैरीजन नहीं है । बलाइन्डली उस जमीदार के खिलाफ किया गया । जब इस किस्म के इन्सीडैन्ट सरकार के नोटिस में आ रहे हैं तो कोई गाइड लाइन्ज दें और सरकार जमींदारो को अश्योरैन्स दे कि अगर सम्बन्धित अधिकारी ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त ऐक्शन लेगे । इन लैप्सज के लिये

डी ० सी ० को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये । एल ०इ ०ओ ० छोटी पोस्ट का होता है । वह तो तहसीलदार के लैवल का होता है इसलिये डी०सी० को जिम्मे– दार ठहराना चाहिये। इसलिये मैं आपके जवाब के साथ बिलकुल सहमत नहीं हूं ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : स्पीकर साहब, यह केस सन 1978 का है । अब ऐक्ट भी चेंज हो चुका है । सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने भी अमैंडमैंट कर दी है और हरियाणा सरकार ने भी निर्णय ले लिया है कि जमींदारों को मार्किट प्राइस दी जायेगी ।

श्री लछमन सिंह : मिनिस्टर साहब क्या अब इस हाउस को इस बात के लिये अश्योर करेंगे कि 1986 के अन्दर आईन्दा जो एक्वीजीशन करेंगे 5– 10 परसैटं की बात को छोड़ कर, वह बिलकुल मार्किट रेट्स पर हीं करेंगे और उसमें 40–50 टाईम्ज की डिसपैरिटी आईन्दा नहीं होगी जैसे कि इन डिमांड्ज में आयी है?

चौधरी कटार सिंह छोकर : स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि 5– 10 परसैंट की बात नहीं है हम तो 15 परसैटं तक मार्किट वैल्यू से ज्यादा कम्पन्सेशन देते हैं । आजकल मार्किट वैल्यू के अलावा 15 परसैटं दिया जाता है, हमने इसका इन्ट्रैस्ट भी बच्चा दिया है और अवधि भी कम कर दी है । दो साल तक अगर उस जमीन को यूज न किया जाये तो हम उसको डि– नोटिफाई कर देते हैं । फिर भी हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे । साहब सिंह सैनी जी

ने, जो बात अभी–अभी सरदार लछमन सिंह ने कही, वही कही है कि आदेश दे दिये गये हैं कि मार्किट प्राइस दी जाये लेकिन कई रेवैन्यू, अक्सर मार्किट प्राइस नही हैं । अगर ऐसा कोई स्पैसिफिक केस होगा तो उसको देख लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात है कि पहले जब सरदार हरपाल सिंह जी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर थे, तो उस वक्त यह बात हुई थी और पिपली रैस्ट हाउस के साथ वाली जमीन का रेट 20 हजार रुपये पर एकड़ असैस किया गया था जबकि उस के आस–पास की जमीन का रेट 60–70 हजार रुपये पर एकड़ का था । उस वक्त यह कमिटमैंट की गयी थी कि अब हम मार्किट प्राईस से कम नहीं देंगे । यह साहब सिंह सैनी जी की बात कहने की बैकग्राउन्ड है । एक दफा आपने 1/10 हिस्सा किसान को दे दिया, उसके बाद आपको पता ही है कि उसका क्या हाल होता है । आप भी जमीदार हैं, मैं भी जमींदार हूं, हम सब को पता है ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : स्पीकर साहब, खास तौर पर हम इस बात को देख लेगे । एक बात इन्होंने नील गाय की बाबत कही । यह प्रौब्लम तो एक पर्टिकुलर एरिया में है । लोकल आफिसर्ज से भी अगर यह बात कहें तो वे इस बात को देख सकते हैं । लाडवा और नलवी कैनाल की बात इन्होंने इम्पोर्टेंट कही कि यह तो मन्जूर हो चुकी हैं, इन का काम शु रू कर दिया जाये । इस बारे में सरकार जल्दी ही काम शुरू करवाने की कोशिश करेगी । पी ०एच ०सीज ० के लिये जमीन देने की बात

भी इन्होंने कही । इन्होंने यह भी कहा कि उस पर काम जल्दी शुरू करवा दिया जाये । हम कोशिश करेंगे कि काम जल्दी शुरू कर दिया जाये । एक बात बहुत से मैम्बरों ने सोशल वैल्फेयर की पैन्शन और दूसरी सहूलियतों के बारे में कही । गरीब आदमियों, बूढे आदमियों और विडोंज को जो सहूलियतें सरकार देती है, उन में बड़ा विलम्ब होता है । एप्लीकेशन्ज की स्क्रूटिनी होती रहती है और वे पैंडिंग पड़ी रहती हैं । तरह–तरह से उसमें डिले किया जाता है । बहुत से केसिज में तो पैन्शन सैंक्शन होने तक एप्ली–कैन्ट एक्सपायर तक हो जाता है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बहुत से मम्बरों ने. उठायी है । इसके बारे में मैं उनको यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमीर मुख्य मती जी ने शुरू में ही यह हिदायत दी थी कि इसके लिये एक कमेटी बनायी जाये । सुरजेवाला साहब, मैं और सोशल वैल्फेयर मिनिस्टर, तीनों उस कमेटी के सदस्य रहे हैं । हमने डिटेल में देखा और इसको एग्जामिन किया । इसके बाद हम कोशिश कर रहे है कि यह जो विलम्ब होता है, जो पैन्शन सैक्शन होने में देरी होती है, उसको कट शौर्ट किया जाये और प्रोसीजर को मोडीफाई किया जाये । श्री लीला कृष्ण जी ने भी यही बात कही । एक बात उन्होंने और कही कि फैमिली प्लानिंग के लिये आज भी लोगों को फोर्स किया जाता है । इसके लिये टारगैट्स बने हुए हैं । इस बारे में मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा, शायद उनको पता भी होगा कि सरकार के हैल्थ डिपार्ट– मैट की ओर से यह सरकुलर भेज दिया गया है कि कहीं पर भी फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग न की जाये और

इसके लिये यह–यह सुविधाएं प्रदान की जायेंगी । हैल्थ डिपार्टमैंट ने इस बात की पूरी जिम्मेवारी ली हुई है कि कहीं पर भी फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग न की जाये । श्री जगदीश नेहरा जी ने कहा कि फलड्ज या किसी और वजह से अब किसी के मकान वगैरह गिर जाते हैं तो उनको जो 400 रुपये दिये जाते हैं, इसको बढ़ाकर एक हजार रुपया कर दिया जाये । इतने कम पैसे से किसी का भी मकान पूरा नहीं बन पाता । स्पीकर साहब, एक–एक आदमी के लिये मकान बनाकर देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । ऐसा सरकार के बस की बात नहीं है । जब गांव में फलड्ज से या किसी नैचुरल क्लैमिटी की वजह से मकान गिर जाते हैं तो टोकन रिलीफ दिया जाता है ताकि लोग अपने गिरे हुए मकानों को फिर से खड़ा कर सकें । इसलिये यह कोई गारन्टिड सहायता नहीं है । फिर भी हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी अगर कोई ऐसी बात हो तो उस व्यक्ति को ज्यादा रिलीफ दिया जाये । (रक बात डी–वाटरिंग के लिये कही गयी । शहरी एरियाज में तो दी– वाटरिंग हो जाती है लेकिन रूरल एरियाज में डी–वाटरिग नहीं होती । इस बात को दिखा लेंगे, कही पर अगर पानी खड़ा होगा तो उसको निकलवा देंगे । मेरी यह जानकारी है और हमारे मुख्य मंत्री जी की शुरू से ही यह पालिसी रही है कि देहात में कहीं पर भी पानी खड़ा नहीं रहना चाहिये । एक ईन्च भी जमीन ऐसी नहीं ' होनी चाहिये जहा पर पानी खड़ा होने की वजह से लोग काश्त न कर सके । इस बारे में हम देख लेगे और इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि देहात में डी– वाटरिंग की

जाये । एक बात उन्होंने यह कही कि एम्पलाईज को डिसमिस करते वक्त पूरी सावधानी बरती जाये । इन्होने यह भी कहा कि किसी भी एम्पलाई को बिना किसी कारण के डिसमिस न किया जाये । पूरी छानबीन होनी चाहिये, उसके बाद ही एक्शन लिया जाना चाहिये । मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि ऐसा ही किया जाता है । पूरी छानबीन करने के बाद ही पनिंशमैंट के तौर पर उसको हटाया जा सकता है । एक बात उन्होंने यह कही कि एक्सीडैंट–क्लेम्ज लिबरली देने चाहियें । मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि क्लेमज के मामले में हम आलरेडी काफी लिबरल हैं । अभी सरकार ने यह तय कर दिया है कि ऐसे क्लेम्ज में 15,000 रुपया तो इनीशियली, विदआउट एनी इन्कवायरी दे दिया जाये । क्लेम तो बाद में डिटरमिन होता रहेगा । एक रीजनल रूरल वैक्स की बात कही कि शेयर कैपिटल बढ़ाने. के लिये साढ़े बारह लाख रुपये की डिमांड रखी गयी है । यह पहले इसलिये एन्वीसेज नही किये जा सके क्योंकि पहले गवर्नमैंट आफ इंडिया ने 25–25 लाख रुपये इनको शेयर कैपिटल दिया था । इनका अथोरार्डज्ड कैपिटल एक–एक करोड़ है । पेड–अप कैपिटल 25 लाख रुपये है । इस 25 लाख रुपये में से 174 के करीब हमने दिया है । हमारा केवल 15 परसैट इसमें कैपिटल है । याद में इन बैंक्स में कुछ लौस हो गया । उसके बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया कि इसका शेयर कैपिटल और बढ़ा दिया जाये और 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया जाये । इससे हमारा शेयर भी बढ़ गया । भारत सरकार ने तो अपना शेयर दे दिया लेकिन हमें यह पैसा

कन्टिनजैसी से देना पड़ा । यह बैंक आम गरीब लोगों की सेवा करते हैं । कन्टिनजैसी के पैसे को रीकूप करने के लिये यह डिमान्ड रखी गयी है । बहिन शान्ति देवी ने यह कहा कि जहां पर फलड्ज नहीं आते वहां पर ड्रेनेच पर पैसा खर्च होने का प्रोवीजन नहीं होना चाहिये । फलड्ज की बजाये शहरों में ड्रेनेज या दूसरे कामों में जहां पर जिस चीज की कमी हो, उसके लिये इस पैसे को डाइवर्ट किया जाए । मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि लोकल बौडीज के पास प्रोवीजन है । मुख्य मती जी की यह हिदायत है कि जो कमजोर लोकल बौडीज हैं, जहां पर कोई इम्पौटेट काम रुके हुए हैं, उनको हम विशेष तौर पर सहायता दें । करनाल होस्पिटल की तो उनकी बड़ी पुरानी मांग. है । उसका उद्घाटन चुका है । रैजीडैंशियल हाउस भी बन चुके हैं. लेकिन ब्लाक्स अभी बन रहे हैं और होस्पिटल की मेन बिल्डिंग भी अभी बन रही है । सरकार इन पर भी जल्दी से जल्दी काम करवाने की कोशिश करेगी । उन्होंने यह कहा कि रिहैबिलीटेशन डिपार्टमैंट के पास कुछ पैसा है जो उन कालोनीज के लिये है जो पार्टीशन के बाद बनी हैं, उस पैसे का सदुपयोग किया जाये । उससे ड्रेनज बना दी जाये या सड़कें बना दी जायें । इन कामों के लिये अलग से पैसा रखा गया होगा । अगर उनके पास कोई पैसा है तो हम देखेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे । करतार देवी जी ने कहा कि लैड एक्वीजीशन का प्रोसीजर बड़ा ही कम्पलीकेटिड है । मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि अब तो इस को बहुत ही सरल कर दिया है । इसके लिये सैट्रल एक्ट है । हम उसको फालो करते हैं । पहले

जो इसमें कमियां थीं, वह अब दूर कर दी गयी हैं । सर्विस बर्खास्त करने की बात उन्होंने भी दोहराई है, उसका जवाब मैं पहले ही वे चुका हूं । इसके साथ–साथ उन्होंने बोहर मे कोडम फाईटर्ज मैमोरियल बनाने की बात कही है । इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने बढ़ा हुआ कम्पनसेशन दे दिया है । अब कोई देरी नहीं होनी चाहिये । हम कोशिश करेंगे कि यह काम जल्दी पूरा हो जाए । जिन हरिजनों ने पांच एकड जमीन खरीदी थी उनको दो–दो हकार रुपया ग्रान्ट दी थी लेकिन बैक से लोन नहीं मिल पाया । इसका कारण यह था कि जो सौदा हुआ था वह जमीन सरप्लस जमीन का हिस्सा थी । सरप्लस जमीन पर बैक ने कर्जा नहीं दिया और उसके बाद जो मालिक थे वे कामयाब हो गए इसलिये वह स्कीम मैटीरियलाइज नहीं हुई । हरिजनों का पूरा ध्यान रखा जाता है उनको जो सरप्लस जमीन अलौट होती है उसके लिये हम पैसा रखते हैं । सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट में जो ऐप्लीकेशन्ज आती हैं उनका प्रोसीजर सिम्पलिफाई करने की बात यहां पर कही गई । स्पीकर साहब, इस प्रोसीजर को सिम्पलीफाई करने की कोशिश की जा रही है । मक्कड़ साहव ने पी ०एच०सी ० पर काम करने के बारे में और जमीन देने के बारे में बात कही है । उसको दिखवा लेंगे और कोशिश करेंगे कि पी ०एच०सी ० का काम जल्दी हो. जाए । उन्होने यह भी कहा कि ग्रामीण बैंक लोगों को परेशान करते हैं, उनको थोड़ा टाइट किया जाए और उनको कंट्रोल किया बाए । हम उनसे तालमेल कर रहे हैं और आशा है कि यह समस्या हल हो जाएगी ओर लोगों की परेशानी

कम हो जाएगी । उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन पर जो बैगर्ज– हैं, वे ऐक्सप्लायट करते हैं, उनको पैन्शन की सुविधा दी जाए । स्पीकर साहब, हरियाणा में कोई भी आदमी, चाहे वह बैगर है, चाहे कोई और है, अगर वह पैन्शन की कंडीशन पूरी करता है तो वह पैन्शन के लिये ऐप्लाई कर सकता है और पैन्शन की सुविधा ले सकता है ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, बैगिंग लीगली प्रोहिविटिड है इसलिये बैगर्ज को पैन्शन नहीं दी जानी चाहिये ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : स्पीकर साहब, हरिजन चौपाल्ज की बात कही गई है । सब ने यही कहा है कि उनके इलाके में इनकी कमी है या ये चौपाल्ज इंकम्पलीट हैं । स्पीकर साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस डिमाण्ड को पूरा किया जाए । चौधरी इन्द्र सिंह नैन ने कहा है कि बरवाला को तहसील बनाया जाए । स्पीकर साहब यह काम प्रोसैस में है । एक उन्हेने यह कहा कि हसनगढ मे टंकी बनाई जाये । उनकी इस डिमांड को दिखवा लेंगे और इस पर काम जल्दी शुरू करवा देंगे । उन्होने यह भी कहा कि मार्किट कमेटीज में जो चालीस परसैंट पैसा जमा होता है वह सड्कों पर लगाया वान। चाहिये । स्पीकर साहब यह सरकार की कमिटमैंट है और यह पैसा सड्कों पर ही लगाया जायेगा । इसमें दिक्कत यह आई कि पैसा दो महीने देर से मिलना शुरू हुआ । चौधरी अजमत खां ने मेवात एरिया में पी ०एच ०सीज ० की कमी और स्टाफ की कमी की बात कही ।

स्पीकर साहब, पी ०एच० सीज ० के लिये नार्म बनाया हुआ है और स्टाफ की जो कमी होती है, वह ऐनरोल करके पूरी कर ली जाती है । उन्होंने कहा कि मन्त्रिगण डिस्क्रीश्नरी ग्रांट अपने ही इलाके में खर्च कर लेते हैं मैं मन्त्रिगण से प्रार्थना करूंगा कि वो अजमत खां की तरफ भी ध्यान दें । उन्होंने सोशल वैलफेयर के लिए जो सुझाव दियो है कि कैम्प लगाए जाएं, यह अच्छा सुझाव है । इस पर विचार किया जाएगा । पानी के टैस्ट करने और उनके एरिया में समय पर वीज सप्लाई करने की बात भी उन्होंने की है। महकमें ने जवाब दिया है कि सी० 306 और डब्ल्यू० एच 47, व 2009 की वैरायटीज के बीजों का स्टाक वहां पहले ही रखा हुआ है । लेट वैरायटी का बीज एच ० बी० 1553, जिसकी 15– 12– 1986 तक बिजाई हो सकती है वह तीन दिन पहले ही डी०सी० की रिक्वैस्ट पर गुड़गांव में भेजा है । स्पीकर साहब, लेट वैरायटी भी अब उनको उपलब्ध होगी और बीज की कोई दिक्कत नहीं होगी । मास्टर राम सिंह ने कहा कि हमारे खादर के एरिया में पी०एच०सीज० कम हैं । स्पीकर साहब, इनका भी खादर का एरिया है और हमारा भी खादर का एरिया । में चौधरी गोवर्धन दास जी से कहूगा कि वे इसका खास ख्याल रखें । रादौर पी०एच०सी० के बारे में कहा गया कि उस पर तीन चार माल से काम शुरू है लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ है । मैं गोवर्धन दास जी से कहूंगा कि जो काम तीन चार साल से अधूरा पड़ा है, उसको पूरा कराएं । हरिजन चौपाल के बारे मैं मैं जवाब दे चुका हूं (व्यवधान) । श्री फूल चन्द जी बहुत तेजी से काम करवा रहे हैं और जो

अधूरे काम हे उनकी तरफ वे विशेष ध्यान देंगे । श्री सूबे सिंह ने कहा कि सूखे के लिये, फलड के लिये यानी नैचुरल कैलेमिटीज के बारे में जब रिलीफ दी जाती है तो उसका माप छोटी यूनिट होनी चाहिए । स्पीकर साहब, कोशिश यही की जाती है कि छोटी से छोटी यूनिट को मापदंड रखा जाए । हम यह देखते हैं कि मिनीमम डैमेज पचास परसैन्ट होना चाहिए । पी ०एच०सीज० में स्टाफ की कमी के बारे में यहां काफी कहा गया गै । स्पीकर साहब कई दफा ऐनरोलमैंट में देरी हो जाती है । यह प्वायंट नोट कर लिया है । जहां से भी डिमान्ड आई है कि वहां पर स्टाफ नहीं एं, उसको पूरा कर दिया जाएगा । स्पीकर साहब, यह भी कहा गया है कि गलियों में पानी भर जाता है इसलिये स्टैण्ड पोस्ट ऐसी । जगह बनाई जाए जहां से पानी आसानी से फ्लो कर जाए, रास्ता खराब न करे । स्पीकर साहब, यह हिदायतें पहले ही जारी हैं कि स्टैण्ड पोस्ट ऐसी जगह बनायी जाए जहां से पानी आसानी से निकल जाए । स्पीकर साहब, इस बात का आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेगे जिससे लोगों को दिक्कत न हो । स्पीकर साहब, यहां कहा गया कि चाइल्डलैस बिडोज को पैन्शन के बारे में प्रायरिटी मिलनी चाहिये ताकि उनको ज्यादा परेशानी न हो ।

श्री भले राम : स्पीकर माहन, ऐसा है कि जो विडो है उसको तो पैन्शन मिलती है लेकिन जो रडवा है उसको पैन्शन नही मिलती (हंसी) ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : ऐसा कोई केस भले राम जी के नोटिस में हो, चाहे कोई लेडी हो, हैन्डीकैप्ड हो, यतीम बच्चा हो, या कोई और,, जिस का कोई स्पोर्टर न हो, ऐसे सभी लोगों के केसिज को हम कंसिडर करते है । ऐसे केसिज में सरकार का काफी पैसा खर्च होता है और इसके लिये सरकार का ध्यान है । मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश भी दिया था कि इस को नये तरीके से देखा जाए । वैसे इस बारे में मुलाना साहब तफसील में बता देंगे ।

लोक निर्माण मन्त्री (श्री फूल चन्द) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में चर्चा करते हुए कई सदस्यों ने अपने अपने बिचार रखे । चौधरी भले राम जी ने यह कहा कि हरिजनों को जो जमीन देने की स्कीम थी, यी केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी थी और हरियाणा सरकार ने इसको बाद में अडाप्ट किया था । इस स्कीम के अन्तर्गत 5 एकड़ कृषि भूमि, खरीदने के लिये दो हजार रुपये तक की सबसिडी दी जाती थी लेकिन बाद में अध्यक्ष महोदय, चूकि स्कीज बढ़ी थी और पैसा कम था, इमलिये हरियाणा सरकार ने खुद अडाप्ट कर लिया और पांच एकड 'मूमि की बजाये उसकी सीलिंग 3 एकड़ तक कर दी लेकिन बैनिफिशरीज नही भले, इसलिये यह स्कीम पिछले दिनों ड्राप हो गयी थी । अब हरियाणा सरकार इसको पहले से ही एग्जामिन कर रही है कि अगर हमको बैनीफिशरीज मलते हैं तो हम इस स्कीम को दोबारा चालू कर देंगे । दूसरी बात उन्होंने कम्पन्सेशन के बारे मैं कही । जिला कल्याण

अधिकारी, फरीदाबाद की जीप 23– 5– 85 को दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी । जे०एम०ए ० फैक्टरी, फरीदाबाद में काम करने वाले श्री 'अवतार सिंह स्वर्ग वाम हो गये थे और उनकी बीवी ने मुआवजे की याचिका दायर कर' दी थी, बस कारण यह केस कोर्ट में चला गया । इस बारे में पूरी जांच कर ली गयी है । साथ में उन्होंने यह भी कहा कि वह गाड़ी ईशोरड नहीं थी । मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार की कोई भी गाड़ी इंशोरड नहीं है । इस कारण से सरकार को यह मुआवजा देना पड़ा है जिसकी स्वीकृति के लिये यह मांग सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है। हमसे अगली बात उन्होंने पैन्शनर्ज के बारे में भी कही कि लोगों को काफी परेशानी होती है । फार्म भरने के बाद, अटैस्ट करवाने के लिये कहीं, बी ०डी ०ओ ०, कहीं डाक्टर और कहीं सी ०एम ० ओ ० के पाम आना जाना पड़ता है और इसी तरह से उनका काफी समय नष्ट हो जाता है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने चौधरी शमशेर सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है । उस कमेटी ने पूर्णतः इस मामले को एग्जामिन किया है । कमेटी इस निर्णय पर पहुंची है कि पैन्शन वाले किटुम को ब्लाक लैवल पर ही निपटा दिया जाए ताकि आगे पैन्शन लेने में देरी न हो । बी० डी ०ओ ० लैवल पर, सभी अधिकारियो की मौजूदगी में फार्मो वगैरह की सभी फारमैलिटीज वहीं पर पूरी करवा ली जाएं जिमसे डी मी ० के लैवल पर मामला तय हो जाए । इस स्कीम को हम बहुत जल्दी ही लागू करने जा पे हैं ।

वित्त मन्त्री (चौधरी कटार सिंह छोकर) : स्पीकर साहब, आप की इजाजत से एक जानकारी मैं लैन्ड ऐक्बीजीशन के बारे में देना चाहूंगा । पहले यह तरीका था कि एक्वायर की मई जमीन का मुआवजा देते वक्त पिछले पांच सालों की सेल–डीडज की एवरेज को देखा जाता था लेकिन अब नयी हिदायतों के हिसाब से कानून में तरमीम होने के बाद यह पांच साल की ऐवरेज वाला तरीका हमने खत्म कर दिया है । अब तो मार्किट वैल्यू ही ली जाती है और उसी के हिसाब से मुआवजा दिया जाता

श्री लछमन सिंह : स्पीकर सर, यह बिल्कुल ठीक है, हाउस में एक्ट मना है । मुझे पता है, पास भी हुआ है । कानून तो है लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है । अब भी डी मी ० ही कीमतें फिक्स करता है । जो रजिस्ट्रीज उस एरियाज में बनी होती हैं, उनको तो वह देखता ही नही है कि यह तो बहुत महंगी है । मैंने इस बारे में रिकवैस्ट भी की थी कि उनको फोर्स किया जाए कि वे इस को प्रैक्टिस में लाए। थ्यूरी में तो सौरी मात ठीक है । किसानों को तो मार्किट वैल्यू अदा नहीं करते, यह मिनिस्टर 'साहब को भी मालूम है औंर आपको भी पता ही हुँ ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : स्पीकर साहब, ऐसी बात नही है । किसानों को मार्किट रेट्स ही देने हैं ।

चौधरी साहब सिंह सैनी : मन्त्री महोदय ने ठीक कहा है कि किसान को, मार्किट वैल्यू के हिसाब से दिया जाता है

लेकिन मैं अपिको एक बात बताना चाहता हूं । लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर खुद मौके पर जाते है । रतगल गांव की एक जमीन का एवार्ड 48 हजार से ऊपर का दिया गया और वह स्वयं एल ०ए ०ओ ० साहब ने जाकर दिया लेकिन दो तीन महीनों के बाद उसी लैन्ड के एक पार्ट का 3० हजार रुपये एवार्ड दिया गया । मुझे नहीं मालूम कि यह एवार्ड कौन से मार्किट रेट के हिसाब से फिक्स किया गया । मुझे इस बात की इतलाह लिखित दी गयी कि डी० सी० साहब ने जो रेट फिक्स किया थी, उसी के हिसाब ' से यह एवार्ड दिया गया है । इस बारे में मन्त्री महोदय क्या जवाब देना चाहते हैं ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : इस सम्बन्ध मे सरकार की ओर से हिदायतें बिलकुल ठीक है लेकिन जैसा कि सरदार लछमन सिंह जी ने कहा कि. कई अफसर कोताही करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, एक बात तो यह है और वह किसी पर्टिकुलर बात में 'देखी जा सकती है । अगर कोई और केस सरकार के नोटिस में 'लाए जाएंगे, बताएंगे तो हम उसे नोट कर लेंगे और एग्जामिन करवा लेंगे ।

श्री लछमन सिंह : कालका में तो यह बात जनरल है ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : जनरल कैसे हो सकती है? सारे अधिकारी प्लायट नहीं कर सकते ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, बहुत सी जमीनों के कम्पन्सेशन के रेट्स हाई कोर्ट में जाकर दोगुने तीन गुने हो गये है ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : आम तौर पर वही हुए हैं जहां बहुत पुरानी एक्वीजीशन हुई हो । पहुत पुराने रेट्स पर कम्पन्सेशन दिया थो । स्पीकर साहब आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में जाने से सालों सारन लग जाते है । यह तो नेचुरल प्रिजम्पशन है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कम्पन्सेशन बढ़ा होगा और हो सकता है किं यह आठ–दस साल फ्रनि केस हो जिनकी ये बात कर रहे हैं या इसके भी बाद के होगे । अगर कोई नया केस इनकी नालिज में है तो ये बताएं, उसको एग्जामिन करवा लेंगे और उसका इलाज भी किया जाएगा । सरकार मानती है कि पहले कम्पन्सैशन किसी और हिसाब से दिया जाता था। जमीन की कीमत उसकी रजिस्ट्री के हिसाब से दी जाती थी । मार्किट वैल्यू आमतौर पर नहीं देते थे । पहले तो मार्किट बैल्यू को डिटरमिन करने का तरीका ही और था । डी०सी० ही कब कुछ करता था । कोई खास बात इनके नोटिस मे हो तो लाएं, हम एग्जामिन करवा लेगे। इन शब्दों के साथ मैं स्पीकर साहब निवेदन करूगा कि इन डिमाड्ज को पास किया जाए । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब मैं डिमांड्ज को बोटिंग के लिये रखूंगा ।

Question is—

That a Supplementary sum tot exceeding Rs. 4,05,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1987 in respeet of Demand No. 4—Revenue.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 11,25,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1987 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिये एडजर्न किया जाता है ।

12.50 बजे

(तत्पश्चात सदन वीरवार 27—11—1986, प्रातः 9.30 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।)